प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खाओं लेकिन पढ़ो।

संत गाडगे बाबा

वर्ष-06, अंक - 26 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 21 मार्च 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

प्रशासनिक सफलता के आंकलन का पैमाना है भगोरिया पर्व

भगोरिया मेले में हुड़दंग को रोकना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर

माही की गूंज, संजय भटेवरा।

झाबुआ। उत्साह, उमंग और उल्लास का पर्व है भगोरिया । एक और जहां जनजातीय वर्ग के लिए मौज-मस्ती और सांस्कृतिक विरासत का पर्व है। वहीं प्रशासन विशेष कर कानून व्यवस्था के आकलन का पैमाना भी है। पुलिस प्रशासन भगोरिया पर्व शांति पूर्वक निपटने पर राहत की सांस लेता है। वही भगोरिया मेले में हुड़दंग को रोकना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित होता है। जिले में अधिकारियों की सफलता का आकलन भी भगोरिया के दौरान अधिकारी व कर्मचारी की सक्रियता के आधार पर किया जाता है।

मस्ती और उमंग के त्योहार होली के पूर्व आने वाले हाट बाजार को अंचल में भगोरिया हाट कहा जाता है। कुछ स्थानों पर इन्हें गुलालिया हाट भी कहा जाता हैं। अलीराजपुर जिले के भगोरिया हाट बाजार बहुत प्रसिद्ध है और इनको देखने के लिए विदेश तक के लोग आते हैं। भगोरिया हाट में अंचल के आदिवासी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं तथा ढोल और मांदल की थाप पर लीन होकर नृत्य करते हैं। समय के साथ-साथ कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं लेकिन भगोरिया हाट में आज भी आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। खेती के कामों से निवृत होकर समाज के लोग बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। तथा इसके बाद ग्रीष्म ऋतु का आगाज हो जाता है और यहां का मजदूर अपना श्रम बेचने और रोजी-रोटी के लिए पलायन कर जाता है। आजादी के अमृतकाल और इतने चुनाव बीत जाने के बाद भी पलायन जिले के लिए मजबूरी है।

'चुनाव प्रचार के लिए बड़ा मंच'

भगोरिया पर्व का राजनीतिक दलों के लिए भी विशेष महत्व है और भगोरिया हाट बाजार राजनीतिक शक्ति आंकने का भी पैमाना है। आमतौर पर भगोरिया पर्व में राजनीतिक दलों द्वारा रैली निकाली जाती है। जिसे स्थानीय भाषा में गैर कहा जाता है और जिस दल की रैली में जितनी ज्यादा बड़ी वह दल उतना ही लोकप्रिय माना जाता है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इन भगोरिया पर्व गैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जमकर शक्ति प्रदर्शन इस पर्व की गैर में होता है। दूसरा पहलू यह है कि राजनीतिक दलों को अपने प्रचार के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं करना पड़ती है। भगोरिया हाट वाले दिन आसपास के गांव के सभी लोग पहुंचते ही है और राजनीतिक दलों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए इंतजाम नहीं करना पड़ते भीड़ उन्हें स्वतः ही मिल जाती है और भीड़ तक वे अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं।

वर्तमान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए ये भगोरिया हाट न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रशासन को भी एक अच्छा मंच उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान आसानी से चलाकर अपनी बात आम जनता तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं।

माही की गूंज परिवार की ओर से सभी पाठकों, संवाददाताओं और क्षेत्र की जनता को होली और भगोरिया पर्व की रंग बिरंगी शुभकामनाएं यह त्यौहार आपके जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आए ये ही आशा।

जीतू पटवारी से नाराज उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के युवा नेताओं में टॉप 3 में शामिल रहे जीतू पटवारी इन दिनों कांग्रेस पार्टी के सबसे विवादित नेता बनते जा रहे हैं। उनकी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति से लेकर अब तक 5 हजार से अधिक कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने उनकी योग्यता और क्षमता पर सवार उठाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

जीतू पटवारी मुझे पहचानते ही नहीं, अपना परिचय देना पड़ता है

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने एक लाइन के इस्तीफा में लिखा, जीतू पटवारी जी, मैं अपने पद एवं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। श्री गुप्ता ने अपनी स्थिति की प्रतिलिपि किसी को नहीं भेजी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। लालचंद गुप्ता ने कहा कि, पिछले 5 वर्ष से कांग्रेस पार्टी में है। पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था। पार्टी के लिए लगातार काम किया लेकिन मुझे पार्टी की रीति और नीति समझ में नहीं आई। पिछले 5 वर्षों में जब भी पार्टी कार्यालय गया तो वहां हर बार अपना परिचय बताना पड़ता था। ऐसे में मुझे बहुत ही अटपटा लगा।

जो विधानसभा चुनाव हार गया उसे लोकसभा का टिकट क्यों दिया

सीधी के एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए टिकट वितरण से नाराज लालचंद गुप्ता ने इशारों ही इशारों में कहा कि, यहां सब कुछ एक ही परिवार को चाहिए। ऐसा उचित नहीं है। जब एक चुनाव हाल ही में हार गए तो ऐसे में उन्हें कैसे टिकट दिया गया। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि वह पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को लोकसभा टिकट मिलने के बाद नाराज चल रहे थे। उनकी यह नाराजगी आज खुलकर सामने आ गई।

आज तय होंगे प्रदेश के 18 लोकसभा उम्मीदवार

भोपाल।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित मध्यप्रदेश की 18 लोकसभा सीटों पर आज कांग्रेस कैंडिडेट तय होंगे। पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में मंगलवार शाम को हुई केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की बैठक में मध्यप्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा नहीं हो पाई।जिसके बाद आज गुरुवार को एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित समिति के तमाम मेंबर मौजूद रहेंगे। मध्यप्रदेश से सीईसी सदस्य ओमकार सिंह मरकाम शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। इससे पहले मंगलवार सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें खड़गे, सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

15 सीटों पर सिंगल नाम तय

एमपी कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद 15 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए हैं। तीन सीटों पर दो-तीन नाम हैं। मंदसौर में नंद किशोर पटेल के साथ ही दिलीप सिंह गुर्जर का नाम है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और पूर्व सांसद रामसेवक सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक के नाम हैं।

राजधानी में 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक, 252 को मिल चुकी हैं नागरिकता

भोपाल। जिले में लगभग 800 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक निवास कर रहे हैं। इनमें से अभी तक लगभग 252 नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। जबकि अन्य सभी को नागरिकता का इंतजार है।

दरअसल, भोपाल कलेक्टर द्वारा इनको नागरिकता दी गई है।अब ऐसे में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने से बचे हुए नागरिकों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि मध्यप्रदेश में नागरिकता देने का अधिकार सिर्फ भोपाल और इंदौर कलेक्टर के पास ही है।

तत्कालीन कलेक्टर ने दी थी नागरिकता

शहर के 17 पाकिस्तानी नागरिकों को पांच महीने पहले भारत की नागरिकता दी गई थी।इन नागरिकों को यहां रहते हुए सात वर्ष का समय पूरा हो चुका था।तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र दिए थे। इसके बाद से शहर में अब तक भारतीय नागरिकता पाने वाले 252 लोग हो गए हैं।बताया जा रहा है कि कुछ आवेदन अब भी लंबित हैं।

अब बचे हुए नागरिकों को सीएए से मिलेगी नागरिकता

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 यानी सीएए को लागू कर दिया है। सीएए को नागरिकता संशोधन कानून कहा गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे शहर में रह रहे बाकि के पाकिस्तानी नागरिकों को अब इस कानून के तहत नागरिकता मिल सकेगी।

16 जिलों के कलेक्टर के पास अधिकार

नागरिकता देने का अधिकार देश के सिर्फ 16 जिलों के कलेक्टर को ही है। मध्यप्रदेश में यह अधिकार भोपाल और इंदौर कलेक्टर के पास हैं। इन कलेक्टरों को दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता देने के अधिकार दिए गए हैं।

मामले में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि, शहर में रह रहे अन्य देशों के नागरिकों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा नजर रखी जाती है। उनसे संबंधित आइबी की रिपोर्ट सहित अन्य डाटा मिलने के बाद नियमानुसार नागरिकता के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

मध्यप्रदेश के पांच जिलों में शराब की एकल प्रणाली हुई समाप्त

शराब ठेकों में प्रतिवर्ष नुकसानी बताने वाला अलकेश बाकलिया ने 15 प्रतिशत बढ़त के साथ 231 करोड़ में लिया शराब का ठेका

माही के गूंज, झाबुआ।
मुज्जमील मंसुरी

उमा भारती की भाजपा सरकार ने 2003-04 में शराब ठेकों की पॉलिसी में बदलाव करते हुए शराब की दुकाने एकल प्रणाली के साथ लॉटरी व्यवस्था के साथ दुकाने दी गई थी। जिसमें तात्कालिक उमा भारती सरकार का उद्देश्य यही रहा था कि, बड़े शराब ठेकेदारों का एकाधिकार व उनका आतंक खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरा उद्देश्य यह भी रहा कि, स्थानीय स्तर के ऐसे व्यक्ति जो शराब बेचकर अपना व्यापार करना चाहते हैं ऐसे छोटे तबके के व्यक्ति भी लॉटरी में अपना भाग्य अजमा सके और उन्हें रोजगार मिल सके। उमा भारती की सरकार का उद्देश्य कुछ हद तक सफल भी रहा जिसमें बड़े ठेकेदारों का एकाधिकार खत्म हो गया था जिसके साथ ही उनके आतंक में भी काफी हद तक कमी भी आई थी।

वही एक समय के बाद एकल प्रणाली में भी शराब की तीन-चार दुकानों का ग्रुप बनाकर लॉटरी सिस्टम से किया था, जिसमें झाबुआ जिले में 10 ग्रुप की देशी- विदेशी की 33 दुकान वही अलीराजपूर जिले की 7 ग्रुप में 19 दुकाने थी।

2023-24 के लिए शासन ने कंपोजिट शराब दुकान का प्रावधान कर शराब ठेकेदार को बड़ा लाभ पहुंचाते हुए एक ही शराब दुकान पर देशी व विदेशी दोनों किस्म की शराब बेचने का प्रावधान किया गया। जिससे ठेकेदार को बड़ी चांदी काटने का मौका मिला। वही मोहन यादव सरकार ने मध्यप्रदेश के पांच जिले झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन व देवास में एकल प्रणाली की व्यवस्था खत्म कर पूरा जिले का एक समूह कर टेंडर में शराब ठेका देने का प्रावधान वर्तमान में कर दिया गया है। 2024-25 हेतु इन पांच जिलों में पहले तो 15 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी के साथ टेंडर आमंत्रित किये। लेकिन 75 प्रतिशत जिले की रेवेन्यू पूरी नहीं होने पर लॉटरी सिस्टम किया गया। जिसमें भी जो शराब ठेकेदार शराब दुकान को महंगी बताकर नुकसानी का सौदा बताकर लाटरी में भाग नही लिया। लेकिन झाबुआ जिले का ऑनलाइन टेंडर जिले के मुख्य शराब का धंधा करने वाले अलकेश बाकलिया ने 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के और ऊपर करीब 231 करोड़ का टेंडर डाल और टेंडर में सिर्फ अलकेश बाकलिया का ही एक टेंडर होने के चलते पूरे जिले का एकाएक ठेकेदार जिले में 20 साल बाद बना है। ऐसे में तय है अलकेश बाकलिया का आतंक अपने एकाधिकार के साथ बताएगा और उसके आतंक का शिकार कहीं न कहीं आम जनता भी होगी यह तय है।

माफिया के आतंक का एक उदाहरण हाल ही में पेटलावद क्षेत्र में देखने में आया है कि उन्होंने कार्रवाई करने वाली एसएसटी टीम पर तक हमला किया है। ऐसे में आम जनता के हाल क्या होंगे यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बता दे अलकेश बाकलिया शराब ठेकों में नुकसानी बताकर सरकार की रेवेन्यू कम करवाकर अपना उल्लू सीधा करता था। नतीजन 2022-23 में झाबुआ जिले का शराब से कुल रेवेन्यू 245 करोड रुपए थी। जबकि 2023-24 में रेवेन्यू घटाकर 200 करोड़ के करीब ठेके गए थे।

वही 2024-25 में पिछ्ली राशि का 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ 231 करोड़ के ऊपर यह ठेका गया। उक्त ठेके में अलकेश बाकलिया के साथ पिंटू भाटिया व केडिया ग्रुप का होना बताया जा रहा है। वही धार जिले की बात करें तो रमेश राय ने 15 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ जिले का ठेका ले लिया जिसमें रमेश राय के साथ नन्ने ग्रुप व गोटू सेठ उज्जैन वाले का नाम शामिल होना बताया जा रहा है।

अलीराजपुर जिले की बात करें तो यहां शराब ठेकेदार के अवैध धंधे को पटकनी लगाने वाले क्षेत्र में राजनीति प्रभाव के साथ अवैध शराब विक्रय करने वाले विरोधी मजबूत है। वहीं उसी राजनीतिक मजबूती के साथ अलीराजपुर जिले को कैबिनेट का दायित्व भी मिल चुका है। ऐसे में आपसी तालमेल बिठाने की जुगत में किसी भी ठेकेदार ने 19 मार्च तक टेंडर नहीं डाला है। नतीजन प्रत्येक टेंडर के साथ ठेके की राशि भी कम होना तय है। ऐसे में अलीराजपुर जिले की 19 शराब की दुकानो का टेंडर कितने में जाएगा व यहां किस तरह से पटकनी देने वाले विरोधियों से ठेकेदार तालमेल बिठाएगा यह तो बाद में ही पता चलेगा।

मूल्य अंतर राहत के बजाय मिले गारंटीशुदा कीमत

सबसे पहले, अच्छी खबर। राजनीति को एक तरफ रखते हुए, छत्तीसगढ़ के किसानों के पास खुश होने के लिए पर्याप्त कारण हैं। गत 12 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के 24.72 लाख धान किसानों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। यह राशि धान किसानों को कमीपूरक भुगतान के रूप में देय थी। पिछले चुनावों से पहले किए गए वादे के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा ने खरीफ 2023-24 सीजन के लिए कॉमन ग्रेड धान के लिए 2,183 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड धान के लिए 2,203 रुपये के खरीद मूल्य पर प्रत्येक किसान से 21 क्विंटल धान खरीदा था।

3,100 रुपये प्रति क्विंटल के खरीद मूल्य के वादे और केंद्र द्वारा एमएसपी मूल्य पर खरीद के वादे के बीच 917 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर अब किसानों के खाते में डाल दिया गया है। यानी प्रतिवर्ष औसत किसान की आय में 1 लाख रुपये की वृद्धि होगी। इस साल लगभग 147 लाख टन की रिकॉर्ड खरीद के साथ, किसान निश्चित रूप से बहुत उत्साहित हैं। हालिया स्थितिजन्य आकलन सर्वे के अनुसार, छत्तीसगढ़ में एक किसान परिवार की औसत मासिक आय 9,677 रुपये है। इसलिए प्रतिवर्ष करीब 1 लाख रुपये की अतिरिक्त आय किसान परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है।

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा गत 14 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न किसान महापंचायत ने सभी फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को जारी रखने का संकल्प लिया है। स्वामीनाथन के सी250 प्रतिशत फार्मूले के अनुसार एमएसपी की गणना की मांग के मुकाबले, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का खरीद मूल्य का भुगतान किया है, जो असल में डॉ. स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा की गयी सिफारिश से भी अधिक है। दूसरी ओर, किसान यूनियनें कहती रही हैं कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा तय किए गए एमएसपी 2,183 रुपये प्रति क्विंटल पर देशभर में धान की खरीद 250 प्रतिशत फार्मूले के जरिये की जाती है। ए2 जेब खर्च है जो किसानों द्वारा फसल उत्पादन में खर्च होता है और एफएल का मतलब पारिवारिक श्रम की आंकी गयी लागत के रूप में है।

लेकिन अगर एमएसपी को स्वामीनाथन के सी250 प्रतिशत के फार्मूले (सी2 का मतलब व्यापक लागत) के अनुसार तैयार किया जाता है, तो खरीफ 2023-24 सीजन के लिए धान की कीमत 2,886.50 रुपये प्रति क्विंटल बन जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वास्तव में इस विपणन सीज़न में धान किसानों को जो भुगतान किया है, वह सी250 प्रतिशत की सिफारिश के बराबर नहीं है, बल्कि वास्तव में सी260 प्रतिशत से अधिक बनता है। यह बढ़ी हुई कीमत राज्य चुनावों से पहले एक रस्साकशी का नतीजा है। इस होड़ में आगे रहने की कोशिश में, कांग्रेस ने 3,200 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया था, प्रत्येक किसान से 20 क्विंटल खरीद के साथ, जबकि भाजपा ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का वादा किया था, लेकिन प्रत्येक एकड़ से खरीदे गए 21 क्विंटल के लिए कीमत सुनिश्चित की थी। यहां पिछली कांग्रेस सरकार के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ देश के बाकी भागों, केरल को छोड़कर, के मुकाबले धान की काफी अधिक कीमत चुका रहा था। साल 2022-23 खरीफ सीज़न के लिए, भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को खरीद मूल्य के अतिरिक्त 9000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया था।

आगामी महीनों में, छत्तीसगढ़ में धान किसानों को दिये जाने वाले ऊंचे रेट अन्य जगहों पर धान किसानों के एकजुट होने के लिए एक मुद्दा बन जाएंगे। यह देखते हुए कि हर साल 23 फसलों के लिए घोषित एमएसपी पूरे देश में एक समान है, मांग यह होगी कि छत्तीसगढ़ मॉडल के सी260 प्रतिशत के आधार पर धान की कीमत में एकरूपता लाई जाए। रोचक यह है कि धान के लिए प्रदान किये जा रहे एमएसपी और सी250 लागत, जिसकी मांग किसान यूनियनें कर रही हैं, के बीच अंतर प्रति क्विंटल 683.5 रुपये बनता है। किसान यूनियनें कहती हैं कि औसत उपज 25 क्विंटल प्रति एकड़ मानते हुए, अगर धान स्वामीनाथन के मूल्य निर्धारण फार्मूले पर खरीदा जाता है तो इसका मतलब होगा किसानों के लिए अतिरिक्त 17,075 रुपये प्रति एकड़, खासकर पंजाब जैसे राज्य में, जहां मंडियों में पूरी फसल की आवक होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में धान के रेट (सी260) के हिसाब से देखें तो मौजूदा एमएसपी के साथ अंतर जिस पर केंद्र सरकार द्वारा खरीद की गयी है, वह तुलनात्मक रूप से 917 रुपये प्रति क्विंटल है।

छत्तीसगढ़ की कीमतों का मतलब है धान के रेट में तुलनात्मक तौर पर सी250 लागत से प्रति क्विंटल 234 रुपये अधिक की बढ़ोतरी। बहरहाल, धान की अधिक कीमत ने किसानों की आशाओं-आकांक्षाओं को जगा दिया है। किसान कह रहे हैं कि अब वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक खर्च करने में सक्षम होंगे, बाजार भी उत्साह से भरे हुए हैं।

छत्तीसगढ़ में विभेदकारी मूल्य तंत्र के जरिये किसानों को किया जा रहा अधिक भुगतान मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों के लिए राहतकारी है, जो लगातार स्वामीनाथन फार्मूले के मुताबिक एमएसपी बढ़ाने पर बाजार विकृति वाला तर्क देते रहे हैं, और अब छत्तीसगढ़ मॉडल द्वारा कायम किये जा रहे नए बेंचमार्क के साथ तो और भी अधिक। वे नहीं चाहते कि एमएसपी बढ़ाया जाए क्योंकि यह उनके दावे के अनुसार बाजारों को विकृत कर देगा, लेकिन अगर राज्य सरकार को भावांतर कीमत के रूप में मूल्य अंतर का भुगतान करना पड़े तो वे खुश हैं। वास्तव में, अर्थशास्त्री नहीं चाहते कि कार्पोरेट और एग्रीबिजनेस कंपनियां कृषि पदार्थों के लिए अधिक कीमत अदा करें।

मेरे विचार में, यह अनुचित है और इसे पॉलिसी के तौर पर लागू नहीं करना चाहिये। यूरोपीय किसानों द्वारा हाल ही में व्यक्त क्षोभ, जिसमें बीते कुछ हफ्तों में 24 देशों के किसानों ने अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किया, से स्पष्ट रूप से सामने आया कि जर्मनी में कृषि वाहनों के लिए डीजल सब्सिडी जैसे इन प्रोत्साहनों को किसी भी स्तर पर राजकोषीय कठिनाइयों या पर्यावरणीय कारकों का हवाला देते हुए वापस लिया जा सकता है। इसलिए एक गारंटीशुदा कीमत की ही जरूरत है।

देविंदर शर्मा

बाजार से फसल उपज की सही कीमत देनी चाहिए। इसे कृषि उपज के लिए कम भुगतान करके और कृषि आय में नुकसान को बजटीय मदद द्वारा कवर करने के लिए छोड़ देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। पहले से ही दुनिया की 54 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में किसानों के लिए उत्पाद मदद के रूप में प्रति वर्ष 851 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च कर रही है ताकि कमी की भरपायी हो सके। यह अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ है जबकि कृषि व्यवसाय से जुड़ी कंपनियां बड़े आराम से धन अर्जित कर रही हैं। ऑक्सफैम के अनुसार, दुनिया में बीते कुछ वर्षों में 68 नए खाद्य अरबपति बने हैं, जिन्हें फूड बैरन कहा जाता है। यह कहना कि उच्च एमएसपी के चलते मुद्रास्फीति अधिक हो जाएगी और बाजारों को विकृत कर देगी, और कुछ नहीं बल्कि जनता में डर पैदा करने का एक प्रयास है। महामारी वर्ष 2020 से शुरू हुए पिछले तीन वर्षों में, कॉर्पोरेट पर रिकॉर्ड मुद्रास्फीति के भंवर के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया है। यहां तक कि आईएमएफ भी स्वीकार करता है कि मुद्रास्फीति में कॉर्पोरेट मुनाफे का हिस्सा, जिसे कॉर्पोरेट लालच के रूप में जाना जाता है, 40 प्रतिशत से अधिक है। कुछ लोग इसे ग्रीडफ्लेशन यानी लालच स्फीति कहते हैं।

मतदाता जागरूकता गतिविधियों का हुआ आयोजन

माही की गूंज, करवड़।

जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में विकासखण्ड पेटलावद के ग्राम करवड़ में स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न गतिविधियां की गई। आंगनवाड़ी एवं स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा मतदान जागरूकता की भारत निर्वाचन आयोग के प्रतीक चिन्ह के साथ आकर्षक रंगोली बनाकर शत प्रतिशत मतदान करने हेतू संदेश दिया गया।

महिलाओ ने मेहंदी लगाकर मतदाता जागरूकता का संदेश भी दिया। जनपद पंचायत पेटलावद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश दीक्षित द्वारा सभी उपस्थितजनों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई और अधिक से अधिक मतदान करने हेतू समझाया गया। ग्राम पंचायत भवन प्रांगण करवड़ से मतदान जागरूकता रैली निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग भगोरिया उत्सव के साथ ढ़ोल ढमाकों के साथ शामिल हुए। जागरूकता रैली में ग्रामवासियों को मतदान का महत्व और उपयोगिता बताते हुए शत प्रतिशत मतदान करने हेतु तख्ती लेकर महिलाओ ने नारे लगाकर प्रेरित किया। आसपास के ग्रामीणों ने रैली मे बाजार चौराहे पर लोक नृत्य करते हुए मतदाता जागरूकता का सदेश भी दिया। कार्यक्रम में सरपंच विकास बाबूलाल गामड, सचिव राजेंद्र सिंह रेडी, रोजगार सहायक संगीता सिनम, हल्का पटवारी संदीप निगवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और करवड़ के निवासी, आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्य उपस्थित रहे।

ग्राम में लगे सीसीटीवी कैमरे

माही की गूंज, करवड़।

विकासखंड पेटलावद के अंतर्गत करवड़ में ग्राम पंचायत के द्वारा 16 स्थान पर लगाए सीसीटीवी कैमरे ग्राम की सुरक्षा को देखते हुए ग्राम पंचायत करवड़ के द्वारा बस स्टैंड रतलाम रोड चांदनी चौक पाटीदार मोहल्ला श्री राम मंदिर अंबे माता मंदिर जैसे कई स्थान पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे जिनका सीधा प्रसारण ग्राम पंचायत में रहेगा एवं मोबाइल से भी कनेक्टिविटी रहेगी

सीसीटीवी लगाए जाने के बाद ग्राम पंचायत की हो रही है प्रशंसा सीसीटीवी कैमरे को ग्राम पंचायत सरपंच विकास बाबूलाल गामड़ ग्राम पंचायत सचिव राजेंद्र रेड्डी रोजगार सहायक संगीता सिनम दशरथ प्रजापत अनोखी प्रजापत लोकेंद्र शर्मा उपस्थित रहे।

निर्वाचन के प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

माही की गूंज, शाजापुर।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के सुव्यवस्थित प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। सभी नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा 20 मार्च को प्रातः 11.00 बजे कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई।

जिसके अनुसार अपर कलेक्टर बीएस सोलंकी को कानून व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन प्रबंधन, शिकायतों की जाँच एवं निराकरण का कार्य सौंपा गया है। इसी तरह सीईओ जिला पंचायत संतोष टैगोर को स्वीप कार्यक्रम के क्रियान्वयन, जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी, मतदान केन्द्र, अनुभाग, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सामान्य व्यवस्था, कार्मिक प्रबंधन, निर्वाचन ड्यूटी संबंधी निराकरण का दायित्व दिया गया है। महिला एवं बाल विकास प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी सुश्री नीलम चौहान को कन्ट्रोल रूम की गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। कार्यपालन यंत्री लोकनिर्माण एमएस डेहरिया को ईव्हीएम प्रबंधन, सामग्री वितरण एवं प्राप्ति प्रबंधन, मतगणना की संपूर्ण तैयारी, मतगणना परिणाम सारणीकरण, टेन्ट-लाईट आदि की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे को निर्वाचन प्रशिक्षण और परिवहन का दायित्व दिया गया है। वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी जीएल गुवाटिया को मतपत्र प्रबंधन, मतदान के लिए ईव्हीएम एवं वीवीपीएटी तैयार कराना, मानदेय वितरण, लोकसभा क्षेत्र के लिए मतपत्र मुद्रण एवं जिला स्तर पर डाकमतपत्र, ईडीसी एवं वरिष्ठ व पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था कराने का दायित्व दिया गया है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को क्रिटिकल घटनाओं की वीडियोग्राफी एवं सीसीटीवी व वेब कॉस्टिंग, रूट चार्ट, एकल खिड़की के माध्यम से अनुमतियां जारी करना, निर्वाचन अभ्यर्थियों के परमिट जारी करना, मतदान उपरांत ईव्हीएम की सीलिंग कर स्ट्रांग रूम में पहुंचाना। लेखा अधिकारी श्रीमती रीना शर्मा को निर्वाचन व्यय लेखा, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख नरेश सोनी को मतदान सामग्री प्रबंधन एवं मतदाता सूची की चिंहित प्रतियां तैयार करना तथा सहायक संचालक जनसम्पर्क अनिल चन्देलकर को मीडिया सेल प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है।

कैबिनेट मंत्री सुश्री भूरिया ने आगजनी से प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया

माही की गूंज ,पेटलावद।

विगत दिनों ग्राम बावड़ी में हुए भीषण आगजनी से आहत परिजनों को ढांढस बधाने के लिए कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया पहुँची। यहा पर मंत्री सुश्री भूरिया ने पीड़ित कान्हा शंभु मैडा, वरसिंह मैडा, दिता डामोर और कमलाबाई डामोर के चार मकानों में निवासरत 11 परिवार के लोग प्रभावित हुए है। आगजनी में पीड़ित परिवारों के बीच केबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने पीड़ित परिवारजनो को ढांढस बंधाते हुए परिवार को नुकसान के लिए शासन से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। सुश्री भूरिया के साथ जनपद अध्यक्ष रमेश सोलंकी, विधानसभा संयोजक हेमन्त भट्ट, वरिष्ठ नेता पुरषोत्तम पाटीदार, सरपंच अश्विन गामड़, उपसरपंच नितेश पारगी, धर्मेंद्र पाटीदार, महामंत्री संजय कहार, पत्रकार संजय लोढ़ा, सुभाष मुलेवा उपस्थित थे।

प्रधान आरक्षक को किया निलंबित

माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पंचाल

बुधवार को सोशल मीडिया पर हुआ एक ऑडियो वायरल जो कि थाना काकनवानी के प्रधान आरक्षक का है। यह ऑडियो वायरल होते एसपी ने प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया। इस वायरल ऑडियो में कितनी सच्चाई है और यह कितना पुराना और कब का है इसकी बिना जांच किए ही प्रधान आरक्षक को निलंबित किये जाने की बात सामने आ रही है। इसमें खास बात यह है कि यह ऑडियो किसका है और इसमें कौन किस से बात कर रहा है और कब का है इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं है।

इस बारे में जब थाना प्रभारी से बात की गई तो बताया गया कि, यह ऑडियो पुराना है और इसमें कौन किससे बात कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस प्रणाली के अनुसार किसी भी मामले में पुलिस को दोषी ठहराया जाता है तो उसे पहले हटाया जाता है उसके पश्चात ही उसकी जांच की जाना बताया।

इस मामले में निलंबित प्रधान आरक्षक लोकेन्द्र नायक से बात की गई तो बताया कि, यह ऑडियो कब का है और किससे कब बात हुई मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है और बिना किसी जांच किए मुझे निलंबित किया गया है।

बगैर लायसेन्स उर्वरक विक्रय पर मामला दर्ज

माही की गूंज, झाबुआ।

कृषक शान्तु पिता भेरा भाबर निवासी महुडीपाडा तहसील पेटलावद के द्वारा शिकायत की जाने पर उर्वरक निरीक्षक पेटलावद के द्वारा क्षेत्र में बगैर उर्वरक लायसेन्स के उर्वरक बेचने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओ का उल्लघंन पाये जाने पर आरोपी रणवीर सिंह पिता परसराम निवासी सिलोली तहसील मेहगाँव जिला भिण्ड (म.प्र.) के विरूद्ध मामला दर्ज कराया गया है।

किसान ,गुणवत्तायुक्त उर्वरक लायसेंसी आदान विक्रेता से ही खरीदें व पक्का बिल अवश्य लेवे। नकली, घटिया व अमानक स्तर के उर्वरक से सावधान रहे। यदि क्षेत्र में बगैर लायसेंसी गांव, मोहल्ले में मोटर साईकिल या कोई अन्य वाहन से किसानों को प्रलोभन देकर उर्वरक बेचता है तो तुरन्त नजदीकी कृषि कार्यालय या जिला कार्यालय को सूचना देवे। बगैर लायसेंसी से उर्वरक क्रय न करे। अमानक स्तर के उर्वरक की गुणवत्ता संदेहप्रद होने पर किसानों को लाभ की तुलना में हानि का शिकार होना पड़ता है। विभाग जिले के किसानों से आग्रह करता है कि, जागरूकता का परिचय देकर ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से बेचने वाले तत्वों से उर्वरक क्रय नहीं करे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय ऐसे व्यक्तियों की सूचना तत्काल विभाग को देवें। जब भी किसी उर्वरक विक्रेता से उर्वरक का क्रय करे तब वह पक्का बिल अवश्य प्राप्त करे।

जघन्य आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना की अध्यक्षता में जघन्य सनसनीखेज चिन्हित आपराधिक प्रकरणों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमे जिला अभियोजन अधिकारी महेश पटेल द्वारा कुल 18 जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों के संबंध में, गवाहों और प्रत्येक प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया। इसी के साथ अवगत कराया गया कि वर्ष 2024 में अबतक की स्थिति में जिले में दोषसिद्धी 100 प्रतिशत है तथा प्रतिकूल टिप्पणी से संबंधित एक भी प्रकरण नहीं है।।उक्त बैठक में अपर कलेक्टर एस.एस.मुजाल्दा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.एल.कुर्वे, अधीक्षक जिला जेल दुष्यंत कुमार पगारे उपस्थित रहे।

भारत में कब शुरू होगी पहली बुलेट ट्रेन...?

नई दिल्ली।

देश में बुलेट ट्रेन को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। लोगों का यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि, 2026 में गुजरात के सूरत से बिलीमोरा तक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और वह शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगी। बता दें कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इसके लिए कई सालों से तेजी से काम चल रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह सिर्फ परिवहन का साधन नहीं है। जब यह चलेगी तो इसके आसपास के सभी शहरों की अर्थव्यवस्था जुड़ जाएगी। मुंबई, ठाणे, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद एक अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र बन जाएंगे। बुलेट ट्रेन 2026 तक तैयार हो जाएगी। यह सबसे पहले सूरत-बिलिमोरा खंड के बीच चलेगी। रेल मंत्री ने दावा किया कि अन्य देशों में 500 किलोमीटर के बीच बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 20 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन भारत में यह काम आठ से 10 वर्ष में ही पूरा कर लिया जाएगा।

बुलेट ट्रेन गुजरात, दादर और नगर हवेली और महाराष्ट्र के बीच चलेगी। इसके लिए कुल 1400 हैक्टेयर की जमीन की जरूरत पड़ रही है। इसमें 156 किलोमीटर महाराष्ट्र का इलाका होगा। इसके अलावा, चार किलोमीटर दादर और नगर हवेली व 384 किलोमीटर गुजरात में ट्रेन चलेगी। भारत इसके लिए इस महीने के आखिरी तक जापान से ई5 सीरीज की छह बुलेट ट्रेनों की खरीद की जाएगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच की दूरी बुलेट ट्रेन महज दो घंटे में ही पूरी कर लेगी। पिछले एक साल में प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न नदियों पर छह पुल पूरे हो चुके हैं और गुजरात में 20 में से सात पुल पूरे हुए हैं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश जरूरी नहीं- केंद्र सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। इस मामले में बुधवार को केंद्र सरकार ने हलफनामा पेश किया। अपनी दलील में सरकार ने कहा कि, यह धारण गलत है कि सलेक्शन पैनल में देश के मुख्य न्यायाधीश का होना अनिवार्य है। और अगर बिना जज की उपस्थिति के पैनल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है तो चुनाव आयोग अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं करेगा। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि यह याचिका राजनीतिक विवाद पैदा करने के लिए डाली गई है।

बुधवार को केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए नए कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध किया। याचिका में तर्क दिया गया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार ने मामले में हलफनामा पेश किया और याचिकाकर्ताओं पर आरोप लगाया कि यह सिर्फ राजनीतिक विवाद पैदा करने के लिए की जा रही कोशिश मात्र है।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में, सरकार ने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को खारिज कर दिया कि चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को 'जल्दबाजी' में नियुक्त किया गया था। सरकार ने तर्क दिया कि देश में इतने बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव होने हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त के भरोसे इस काम को पूरा किया जाना किसी भी सूरत में संभव नहीं है।

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा- यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि चुनाव आयोग तभी स्वतंत्र रूप से काम करेगा, जब नियुक्ति पैनल में कोई जज हो। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। सरकार ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा सुप्रीॉम कोर्ट में दायर याचिका के जवाब में हलफनामा पेश किया था। याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को सिर्फ कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना स्वस्थ, स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा हो सकता है।

कार-बाइक भिंडतः बाइक चला रहे दो युवकों की घटना स्थल पर मौत

माही की गूंज, खवासा। सुनिल सोंलकी

बुधवार रात्रि में खवासा-बामनिया मार्ग पर कार व बाइक की आमने-सामने टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की घटना स्थल पर मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी की बाइक के परखच्चे उड़ गए। वही घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि, एक युवक का बाया हाथ भी कट कर अलग हो चुका है। दोनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है की बाईक सिधे ही कार में आकर घुस गई। कार चला रहे ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है । पुलिस घटनास्थल पर पहुच पंचनामा बनाकर मामले की तस्दीक की जा रही है ।

क्या दलित आदिवासी आईएएस, आईपीएस को आरक्षण से किया जाएगा बाहर...!

दलित आदिवासी मंत्री सांसद और विधायक भी होंगे आरक्षण की श्रेणी से बाहर...?

जी हां, आपने जो ऊपर पढ़ा हैं, वो भारत में न्यायपालिका की टिप्पणी का हिस्सा माना जा सकता हैं। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति नाथ का कहना है कि, दलित आदिवासी में जो उपजातियां बेहतर स्थिति में है उन्हें सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए।

7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इस सवाल की जांच कर रहा है कि, क्या राज्य अनुसूचित जाति के भीतर उपजातियों की पहचान कर ऊपवर्गीकरण कर सकते हैं जो आरक्षण के पात्र हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने पूछा कि, आरक्षण सूची से कोई बाहर क्यों नहीं होना चाहिए...? न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि, वे उपजातियां जो अभी पिछड़ी है, उन्हे आरक्षण दिया जाए। 7 सदस्यीय बेच के समक्ष आए सवाल पर एक टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई ने कहा कि, जो आईएएस/आईपीएस बन जाते हैं उनके बच्चे वंचित नहीं रहते हैं, जबकी जितना उनके वर्ग के ही गांव के अन्य लोग वंचित रह जाते है।

इस टिप्पणी का क्या सीधे-सीधे यह अर्थ नहीं निकलता है कि, दलित आदिवासी में जो आईएएस, आईपीएस बन गया उनके बच्चों को आरक्षण से अलग कर दिया जाए...? क्या यह टिप्पणी आगे चलकर दलित- आदिवासी मंत्रियों, सांसद,विधायकों पर लागू नहीं होती है...? मेरे ख्याल से होती है। इसका मतलब न्यायमूर्ति बीआर गवई ने एसटी, एससी आरक्षण में क्रिमिलेयर व्यवस्था लागू करने की बात कही जिससे दलित-आदिवासी में अपने ही वर्ग में दो फाड़ हो जायेंगे जो एक दूसरे के विरोधी होंगे।

वही ओबीसी में क्रिमिलेयर व्यवस्था इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद ओबीसी आरक्षण में डाला गया। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों में क्रिमिलेयर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ओबीसी में क्रिमिलेयर होने से ओबीसी समाज को यह नुकसान हुआ कि, ओबीसी आरक्षण प्राप्त कर आईएएस,आईपीएस बनने वाले आरक्षण की व्यवस्था से क्रिमिलेयर की वजह से बाहर कर दिए जाते हैं। जिस वजह से उच्च पदों पर ओबीसी आरक्षण का लाभ लेकर चयन होने वाले ओबीसी वर्ग की आरक्षण की समस्याओं पर चुप्पी साध लेते हैं और इसी वजह से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हो पाई।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की टिप्पणी भी कहीं न कहीं एसटी,एससी वर्ग के आईएएस ,आईपीएस को आरक्षण की श्रेणी से बाहर करने के बाद शायद दलित आदिवासी सांसद, विधायकों की संतानों को भी आरक्षण से वंचित करने की योजना का एक भाग लगता है ! आरक्षण कोई गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह एक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। क्या दलित आदिवासी आईएएस-आईपीएस-सांसद बनने से उनके साथ जातिगत भेदभाव खत्म हो जाते हैं? दलितों और आदिवासियों के साथ सदियों से अत्याचार होते आ रहे हैं और संविधान लागु होने के बाद भी ये अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। अगर दलित-आदिवासी आईएएस,आईपीएस, मंत्री, सांसद, विधायक अगर आरक्षण से बाहर हो गए तो दलित-आदिवासी समाज पर होने वाले अत्याचार पर बोलेगा कौन...? न्यायमूर्ति बीआर गवई की टिप्पणी कहीं न कहीं एसटी-एससी आरक्षण में क्रिमिलेयर लागू कर इस वर्ग में अपने ही खिलाफ इस वर्ग को खड़ा करने की साजिश का एक हिस्सा लगता है। जिसका व्यक्तिगत रूप से विरोध करते है। एसटी-एससी में क्रिमिलेयर जैसी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और ओबीसी में भी क्रिमिलेयर वाली व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए।

डा.नरेश पटेल
लेखक ओबीसी अधिकार मंच राष्ट्रीय संयोजक हैं बांसवाड़ा

जिले में 100 से अधिक जगह पर हनुमान चालीसा केंद्र स्थापित होंगे- प्रांत मंत्री चौहान

माही की गूंज , पेटलावद।

अन्तरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद,राष्ट्रीय बजरंग दल (मालवा प्रांत) झाबुआ जिला की वृद बैठक गायत्री मंदिर परिसर पेटलावद में रखी गई है। जिसमे संगठन विस्तार एवं संगठन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि अन्तरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद मालवा प्रांत संगठन महामंत्री संजय यादव एवं राष्ट्रीय बजरंग दल मालवा प्रांत मंत्री महेश कांत चौहान मुख्यरूप से उपस्थित रहें। राष्ट्रीय बजरंग दल के मालवा प्रांत मंत्री महेशकांत चौहान ने सम्बोधित करते हुए सभी जिला पदाधिकारी, कार्यकर्त्ताओ का मार्गदर्शन किया, जिसमे सभी हिंदुओ को संगठित होने का कहा। पिछ्ले माह संगठन कार्य की समीक्षा और कार्यक्रम का विवरण दिया गया।

प्रान्त संगठन महामंत्री संजय यादव ने बताया कि, हिन्दू समृद्धि सुरक्षा सम्मान हिन्दू ही आगे के लक्ष्य को लेकर चल रहे अन्तरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संस्थापक एवं अध्यक्ष हिंदू हृदय सम्राट डॉ. प्रवीण भाई तोगड़िया के आह्वान पर हिंदू समाज को संगठित कर साप्ताहिक शनिवार, मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ प्रत्येक कार्यकर्ता को चलाना है। बैठक में संकल्प लिया गया है की हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करेंगे। झाबुआ जिले में पेटलावद, सारंगी, रायपुरिया, जामली, बोडायता,बाछीखेड़ा,थांदला, मेघनगर, झाबुआ ग्रामीण व झाबुआ में मिलकर 100 से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेंगे। इसी के साथ में संगठन को गति देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दायित्व की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद पेटलावद तहसील अध्यक्ष दीपक पाटीदार, राष्ट्रीय बजरंग दल ,पेटलावद तहसील उपाध्यक्ष राज कुमार टांक, राष्ट्रीय बजरंग दल मेघनगर तहसील अध्यक्ष एवं झाबुआ ग्रामीण अध्यक्ष विक्रम सिंह भूरिया पदाधिकारी की नवीन दायित्व की घोषणा की गई। इस बैठक में उपस्थिति राष्ट्रीय किसान परिषद जिला अध्यक्ष वाशु देव आंजना, जिला मंत्री पुष्पराज सिंह नरवरिया, तहसील कार्यकारी अध्यक्ष सुनील सोनी, तहसील महामंत्री सुधीर चौधरी, तहसील उपाध्यक्ष बाबूलाल गुर्जर, तहसील मंत्री विशाल वर्मा,कलसिंह महाराज,कलम मुनिया, थावा भूरिया,हेमराज मैडा, शेलू डामर आदि पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे। बैठक का आरम्भ अहिप जिला अध्यक्ष महेश कांत चौहान द्वारा तीन बार ओम के जाप के साथ 13 बार विजय महामंत्र श्री राम ,जय राम जय जय, राम से बैठक प्रारंभ की गई। बैठक का समापन जिला मंत्री पुष्पराज सिंह नरवरिया ने किया।

इस वर्ष फीका रहा भगोरिया

माही की गूंज, थांदला।

भगोरिया पर्व पर मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य, राज्यसभा सांसद सुमैरसिह सोलंकी का थांदला भगोरिया आगमन पर भाजपा प्रदेश, जिला, व मंडल पदाधिकारियों ने स्वागत किया। भगोरिया चल सामारोह पुराने मंडी से प्रारंभ होकर तेजाजी मंदिर होते हुए पीपली चोराहा, आजाद चौक, अंबे माता चौराहा होते हुए प्राचीन हनुमान अष्ट मंदिर पर समापन हुआ। चल समारोह में मुख्य अतिथि सहित सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता ने साफ़ा बांधे नाचते-गाते हुए भगोरिया गुलालीया पर्व धूमधाम से मनाया। प्रशासन की सराहनीय भूमिका रही, चप्पे-चप्पे पर पुलिस मोजुद रही और शांतिपूर्ण तरीके से भगोरिया पर्व मनाया गया।

प्रजापति समाज धर्म जागरण रथ यात्रा का हुआ आगमन, समाजजनों ने निकाली शोभा यात्रा

माही की गूंज, सारंगी।

प्रजापति समाज के महंत स्वामी रामनारायण जी महाराज द्वारा निकाली जा रही श्री श्रीयादे माता प्रजापति समाज धर्म जागरण रथ यात्रा रविवार को सारंगी पहुँची। रथ यात्रा के सारंगी पहुंचने पर प्रजापति समाज द्वारा सारंगी बस स्टेण्ड से शीतला माता मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में समाज के बुजुर्ग, युवा, महिलाएं व युवतियां भी शामिल थी। महंत स्वामी रामनारायण जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करते हुए निकलें। साथ ही श्री श्रीयादे माता का रथ भी यात्रा में मौजूद रहा। यात्रा शीतला माता मंदिर पहुंचकर धर्म सभा मे परिवर्तित हुई। धर्मसभा में संबोधित करते हुए समाज के महंत स्वामी रामनारायण जी महाराज ने समाजजनों से संगठित रहने का आव्हान करते हुए कहा कि, समाज के बेटे और बेटी को समान रूप से शिक्षा दे, क्योकि अगर समाज के बेटा-बेटी शिक्षित होंगे तो ही आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी।

करवड़ में गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ हुआ

माही की गूंज, करवड़। पेटलावद विकासखंड के अंतर्गत बामनिया शाखा में आने वाली आदिम जाति सेवा सहकारी सस्था करवड़ में शासन द्वारा गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया जिन किसानों का पंजीयन हो गया है उन किसानों का गेहूं खरीदारी केंद्र पर तोला जाएगा समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों को पैसा दिया जाएगा इस कार्यक्रम में उपस्थित बामनिया शाखा प्रबंधक गुलाब सिंह निनामा के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्या अर्पण किया एवं तोला कांटा की विधि विधान से पूजा की इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था मैनेजर रमेश चंद्र सोलंकी पूर्व समिति अध्यक्ष लूनचंद गामड़ सेल्समेन लक्ष्मण सिंह पवार कंप्यूटर ऑपरेटर चेतन पाटीदार तुला वटी विकास पाटीदार सुखराम भाई एवं आसपास के किसान उपस्थित रहे।

कलेक्टर, एसपी ने अंतर्राज्यीय सीमा का किया निरीक्षण

माही की गूंज, थांदला।

लोकसभा निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर नेहा मीना और पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ला ने थांदला नगर पुरानी मंडी पर पहुँच कर आदिवासी उत्सव भगोरिया पर्व पर प्रशासनिक स्थिति का जायजा लिया। दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ के ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें लोकतंत्र के महापर्व की जानकारी देते हुए आगामी 13 मई को मतदान करने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंनें यहाँ से लगी समीपस्थ मध्यप्रदेश - राजस्थान अन्तरर्राज्यीय सीमा कुशलगढ़ - थांदला मार्ग के ग्राम टिमरवानी बॉर्डर का दौरा करते हुए यहाँ सीसीटीवी की उपलब्धता, ड्यूटी देने पर तैनात किये गए गठित दल के साथ टेंट, पीने के पानी, रुकने की व्यवस्था आदि आवश्यकताओं की जानकारी लेते हुए उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी तरुण जैन, एसडीओपी रविन्द्र सिंह राठी, तहसीलदार अनिल बघेल, थाना प्रभारी दिनेश रावत आदि को आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सख्त है व सभी अन्तरर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस जवानों के साथ निर्वाचन आयोग की एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी टीमों द्वारा सतत मोनिटरिंग करते हुए संदिग्ध गतिविधियों जैसे शराब तस्करी, हथियार तस्करी के साथ पैसों के हवालों आदि पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैलगाड़ी में सवार होकर विवाह में बारात लेकर मंडप में पहुँचा दूल्हा

बिना डीजे के पारंपरिक ढोल-मांदल पर झूमते गाते निकली बारात

माही की गूंज , पेटलावद।

वर्तमान में अंचल में शादी विवाह का दौर चल रहा है । मुख्य सड़कों से गुजर पर चार पहिया और दुपहिया वाहनों का काफिला डीजे के साथ दिखना आम बात हो गई । आदिवासी परंपरागत विवाह गीतों ओर संगीत साधनों की जगह डीजे ओर बेंड ने ले ली है । मगर आज के आधुनिक जमाने में पेटलावद की ग्राम पंचायत काजबी के छोटे से गांव लालारुण्डी में एक अनोखी बारात निकाली। लालारुंडी गांव के लोग उस वक्त दंग रह गए जब एक दूल्हा बैलगाड़ी पर सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने निकला। इस बारात में कोई वाहन नही सिर्फ बेलगाड़ी थी। पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ बैलगाड़ी पर निकले इस काफिला देखकर हर शख्स की नजर बारात पर टिक गई। इस बारात की सबसे खास बात यह थी कि यह बारात पूरी तरह से महंगी- महंगी गाड़ियों के बजाय बैलगाड़ी से रवाना हुई।

दरअसल गांव लालारुंडी के दशरथ निनामा के पुत्र ऋषभ निनामा की शादी ग्राम सुवरपाड़ा में तय हुई थी। दूल्हे ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कुछ अलग करने का विचार किया। इसलिए उसने वर्षो पुराने अंदाज में बैलगाड़ी पर अपनी बारात ले जाने का फैसला किया। उसने बैलगाड़ी को अपने और बारातियों के लिए चुना। जब बैलगाड़ी पर बारात निकाली तो हर शख्स की नजर बारात पर टिक गई। इस तरह बारात ले जाने को लेकर ऋषभ ने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि हमारे समाज में आधुनिकता की इस चकाचौंध दौड़ में शादियां बहुत महंगी होती जा रही है। लोग दिखावे के लिए दर्जनों महंगी महंगी गाड़ियां किराए से कर लेते है और डीजे के साथ बारात निकालते है। इस तरह जो लंबा खर्च शादी में होता है उसका बोझ दूल्हे के पिता पर ही आता है। लोग अपनी मूल संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आधुनिक संस्कृति में रमते जा रहे हैं। इस कारण डीजे के कानफोडू साउंड और तामझाम में हमारी संस्कृति विलुप्त होते जा रही है। आजकल यह एक फैशन बन गया है कि जिस भी युवक की शादी होती है। उसकी शादी में लंबा काफिला दिखना चाहिए, लेकिन मैंने मेरे पिता पर बोझ न आए इसलिए सभी आधुनिकता की चकाचौंध को त्याग कर पुराने रितिरिवाज से अपनी बारात निकालने का फैसला किया। बता दें कि दूल्हा खुद एक किसान है। उसके पिता भी किसान ही हैं। उसने अपनी बारात अपने घर से निकाली और दुल्हन के दरवाजे अनोखे अंदाज में पहुंचा। इस काफिले को देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। बैलगाड़ी किसान की पहचान होती है। इसीलिए इस तरह बेटे की बारात निकालने का प्लान बनाया गया। बारात लोक नृत्य मंडली ढोल मांदल, झाझ, मजीरा के साथ निकली।

दिन में निकली इस बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। आदिवासी समाज की संस्कृति को संजोये रखने के इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है।

संपादकीय

फिर-फिर पुतिन

एक बार फिर ब्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। वे पांचवीं बार राष्ट्रपति बने हैं। जो बताता है कि दो वर्ष पूर्व यूक्रेन युद्ध शुरू करने के चलते पूरी दुनिया के निशाने पर आने वाले पुतिन का अपने देश रूस में एकछत्र राज्य है। वैसे खुफिया एजेंसी प्रमुख से लेकर राष्ट्रपति बनने तक पुतिन की निरंकुश सत्ता लगातार परवान चढ़ती रही है। पश्चिमी देशों की सुविधा के अनुरूप लाई गई उदारीकरण व खुलेपन की वैश्विक नीतियों से सोवियत संघ के बिखराव के बाद आहत रूसी राष्ट्रवाद को पुतिन ने अपने तरीके से सींचा। शासन, चुनाव तंत्र और मीडिया पर वर्चस्व रखने वाले पुतिन ने अपनी सुविधा का लोकतंत्र गढ़ा। यही वजह है कि पांचवीं बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे पुतिन का राष्ट्रपति बनना अटल सत्य था। उनके सामने जो तीन उम्मीदवार थे, कहा जाता है कि उन्हें क्रेमलिन की ओर से ही खड़ा किया गया था। वे पुतिन की तारीफ में कसीदे पढ़ते देखे गए। वह बात अलग है कि कुल वोट का 87 फीसदी हिस्सा मिलने के बाद पुतिन ने कहा कि रूसी लोकतंत्र कई पश्चिमी देशों के लोकतंत्र से ज्यादा सशक्त है। लेकिन जैसा कि पश्चिमी जगत आरोप लगाता रहा है कि पुतिन ने अपने तमाम विरोधियों को ठिकाने लगा दिया था और वास्तविक युद्ध विरोधियों को चुनाव लड़ने की इजाजत तक नहीं दी गई। वे उनके सशक्त विरोधी रहे एलेक्सी नवेलनी की हालिया संदिग्ध मौत को इसी कड़ी का हिस्सा बताते हैं। नवेलनी समर्थकों ने रूस के शहरों व पश्चिमी देशों में रूसी दूतावासों के बाहर विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से मतदान किया। उनका मानना रहा है कि रूस में एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं था, जिसकी विश्वसनीयता मानी जा सके। वहीं पश्चिमी देश कुछ लोगों की गिरफ्तारी का भी आरोप लगाते हुए कहते हैं कि चुनाव स्वतंत्र, पारदर्शी व निष्पक्ष नहीं रहा। दूसरी ओर जर्मनी जहां इन चुनावों को सेंसरशिप के बीच छद्म चुनाव बता रहा है,वहीं ब्रिटेन का आरोप है कि रूस द्वारा यूक्रेन के अधिकृत इलाकों में अवैधानिक तरीके से चुनाव कराए गए।

नि:संदेह, साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में पूंजीवाद का भय दिखाकर राष्ट्रवाद की चाशनी में जिस तरह के लोकतंत्र को परिभाषित किया जा रहा है, उसकी बानगी हमारे पड़ोसी देश चीन में भी नजर आती है। जहां सत्ता से जुड़े प्रतिष्ठानों व सेना पर अधिकार करके मनमाफिक कार्यकाल के लिये चुनावों का प्रपंच रचा जाता है। सही मायनों में उस चुनाव का वास्तविक लोकंतत्र से कोई लेना-देना नहीं होता। बल्कि निरंकुश सत्ता को तार्किक बनाने की कवायद में लोकतंत्र का प्रहसन ही किया जाता है। दरअसल, निरंकुश सत्ताधीश सरकारी सूचना माध्यमों पर वर्चस्व कायम कर और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर सूचना के तमाम स्वतंत्र स्रोतों का प्रवाह बंद कर देते हैं, जिससे वास्तविक सूचना व लोकतांत्रिक आजादी से लोग वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में जारी दो साल लंबे युद्ध में रूस ने बड़ी कीमत न चुकायी हो, लेकिन सूचना माध्यमों से युद्ध में बढ़त के तौर पर दर्शाया जा रहा है। यह विडंबना ही है कि उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर निरंकुश सत्ताओं को पोषण का अनवरत सिलसिला दुनिया के तमाम देशों में जारी रहा है। विडंबना यही है कि सामाजिक मूल्यो में गिरावट, सत्ता लोलुपता और दोहरे मापदंडों से जहां वास्तविक लोकतंत्रों की स्थापना कठिन होती है, वहीं महत्वाकांक्षी और सशक्त नेता इसी लोकतंत्र को अपनी ताकत में बदल देते हैं। उनकी सत्ताएं इसी छद्म लोकतंत्र के सहारे ही आगे बढ़ती हैं। आधुनिक तकनीक व सूचना माध्यमों पर उनका वर्चस्व सही मायनों में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के मार्ग में बाधक बन जाता है। प्रतिरोध में उठे कुछ बुलंद स्वर कभी-कभी ये अहसास कराते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुदरत के नियम अपनी जगह होते हैं। ये घटनाक्रम दुनिया भर के लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिये भी सबक होते हैं कि लोकतंत्र का भविष्य नागरिकों की जागरूकता, जवाबदेही और जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। उनकी उदासीनता पारदर्शी व सशक्त लोकतंत्र के विकास में बाधक होती है। सही मायनों में लोकतंत्र की सार्थकता चुनाव प्रक्रिया में सबको समान अवसर देने में है।

दावों-वादों-गारंटियों की पड़ताल करे मतदाता

विश्वनाथ सचदेव

चुनाव आयोग द्वारा आम-चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। जुलूस, नारे, नेताओं के बयान, रोड शो आदि का शोर जोरों से सुनाई देने लगा है। इस सबको चुनाव की विधिवत शुरुआत भले ही कह लें, पर हकीकत यह है कि अब हमारे देश में चुनाव शुरू नहीं होते, चलते रहते हैं। एक अनवरत प्रक्रिया बन गये हैं चुनाव और इस प्रक्रिया के बनने में सबसे बड़ा योगदान सत्तारूढ़ दल भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री का है। देखा जाए तो यह स्थिति अपने आप में कुछ ग़लत भी नहीं है, आखिर चुनाव जनतंत्र का उत्सव होते हैं, और ईमानदारी से लड़ी गई चुनावी लड़ाई जनतंत्र की सफलता और सार्थकता को ही प्रमाणित करते हैं। पर हमारी हकीकत यह भी है कि चुनाव में सब कुछ कहने-करने को स्वीकार्य मान लिया गया है। सिद्धांतहीन राजनीतिक समझौते और आधारहीन दावे और खोखले वादे दुर्भाग्य से हमारे जनतंत्र की एक पहचान बनते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जनता इन दावों-वादों, गारंटियों की पड़ताल करती रहे।

ऐसा ही एक दावा विकास का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास के मोर्चे पर हमने कई सफलताएं अर्जित की हैं। देश में सड़कों का निर्माण जिस गति से हो रहा है, वह अपने आप में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। रेल-मार्गों का विकास और रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि भी ऐसी ही एक सफलता है। रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल तक की हमारी उड़ानें किसी भी भारतीय के मन में गर्व का अहसास जगा सकती है। विकास के इस संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े भरोसा दिलाने वाले हैं। लगभग साढ़े आठ प्रतिशत जीडीपी का आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। लेकिन विकास की सार्थकता तभी बनती है जब यह विकास बेहतर जिंदगी में परिवर्तित हो। बेहतर जिंदगी का मतलब है हर क्षेत्र में आज बीते हुए कल से बेहतर दिखाई दे और आने वाले कल के लिए उम्मीदें जगाने वाला हो।

यह सही है कि हमारा जीडीपी एक सम्मानजनक स्तर पर है। यह भी सही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम दुनिया के अनेक देशों से कहीं आगे हैं। आज हमारी अर्थ-व्यवस्था दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थ-व्यवस्था है। हमारा लक्ष्य पांचवें से तीसरे पायदान पर पहुंचने का है। पर सवाल वही हैदृविकास की यह गति बेहतर जिंदगी में परिवर्तित हो रही है या नहीं? जनवरी, 2024 में हमारी बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत थी। फरवरी में यह प्रतिशत बढ़कर आठ हो गया। थोड़ा-सा और खंगालें तो पता चलता है इस संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति और बुरी है। वहां बेरोज़गारी का प्रतिशत क्रमशः 5.8 और 7.8 था। इसमें कोई संदेह नहीं कि शहरी क्षेत्र में इस दौरान यह आंकड़ा 8.9 प्रतिशत से कम होकर 8.5 प्रतिशत हो गया था। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दो-तिहाई क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है। महंगाई के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में जिंदगी की कठिनाइयां कम नहीं हो रहीं, उल्टे बढ़ती जा रही हैं।

महंगाई और बेरोज़गारी का यह मुद्दा आम-चुनाव का बड़ा मुद्दा बनना चाहिए था। पर अभी तक विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने में सफल नहीं हो पाया है। वास्तविकता तो यह है कि चुनावी मुद्दों के नाम पर अनावश्यक मुद्दे उछाले जा रहे हैं। एक उदाहरण

देखेंदृमुंबई की एक सभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 'एक शक्ति' का मुकाबला करने की बात कही। उनका आशय ग़लत ताकतों से लड़ने का रहा होगा। पर दूसरे ही दिन सत्तारूढ़ पक्ष ने इस 'शक्ति' को 'शक्ति की देवी' से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत की एक चुनावी सभा में घोषणा कर दी कि वे नारी-शक्ति की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर देंगे। उन्हें महारत हासिल है इस तरह के मुद्दे लपकने में और इसका लाभ उठाने में। पिछले दो आम-चुनावों में हमने देखा था कि कैसे 'चायवाला' और 'नीच' शब्द उनके लिए चुनावी-वरदान बन गया था।

होना तो यह चाहिए कि चुनाव में सत्तारूढ़ पक्ष अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा मतदाता के समक्ष रखे और विपक्ष सत्तारूढ़ पक्ष की कमियों-असफलताओं को उजागर करके बेहतर नीतियों के आधार पर वोट मांगे, लेकिन हो यह रहा है कि आकर्षक वादों और आधारहीन दावों के बल पर चुनाव लड़ा-लड़ाया जा रहा है। ऐसे में मतदाता का दायित्व बनता है कि वह सत्ता के लिए लड़ने वाले राजनेताओं और राजनीतिक दलों से उनके दावों-वादों के आधार के बारे में पूछे। उनसे कहे कि आकर्षक शब्दों और लोक-लुभावन शैली से उसे भरमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और न ही राजनीतिक दलों को यह मानना चाहिए कि मतदाता उनकी मुट्ठी में है।

आज देश के मतदाता को सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछना है कि उसकी बेहतरी के लिए उसके पास क्या योजना है? विकास जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया का नाम है। विकास का वास्तविक अर्थ है मानव-जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सही मायनों में विकास तब होता है जब जीवन के हर स्तर में बेहतरी दिखे, जनता का आत्म-विश्वास बढ़े, स्वतंत्रता अपनी संपूर्णता में जीवन को संवारती दिखे। क्या ऐसा हो रहा है, यह सवाल मतदाता को अपने आप से पूछना होगा। इस प्रश्न का सम्यक उत्तर ही उसे सही के पक्ष में खड़े होने का अवसर देगा।

यह सवाल तो मतदाता के मन में उठना ही चाहिए कि यह कैसा विकास है जिसमें एक तरफ तो विश्व स्तर पर पांचवें पायदान से तीसरे पायदान तक पहुंचाने के दावे और वादे किए जा रहे हैं, और दूसरी ओर देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने की आवश्यकता पड़ रही है? आज देश के मतदाता को शक्ति का अर्थ समझने-समझाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी हर कोशिश को उसे भरमाने की एक चाल के रूप में ही देखा जाना चाहिए। चुनाव सही और उचित मुद्दों के आधार पर लड़े जाएंगे, तभी हमारा जनतंत्र सार्थक सिद्ध हो सकता है। मतदाता का अधिकार है कि उसके समक्ष बेहतर विकल्प प्रस्तुत किए जाएं, लच्छेदार भाषा और आकर्षक नारे शायद चुनाव जीतने में कुछ मददगार सिद्ध हो भी जाएं, पर जनतंत्र की सार्थकता का तकाज़ा है कि मतदाता को भरमाया नहीं जाये, उसे जागरूक बनाया जाये। यह जागरूकता ही जनतंत्र का औचित्य सिद्ध करती है।

राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र निर्वाचित प्रतिनिधियों का दल-बदल

सनत कुमार जैन

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी। सभी राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र तैयार किये जा रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के लिए घोषणा कर अपने लिए समर्थन जुटाया जाता है। चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी घोषणाओं के माध्यम से मतदाताओं का विश्वास अर्जित करते हैं। मतदाता भी राजनीतिक दलों की विचारधारा और उनके द्वारा की गई घोषणाओं के आधार पर मतदान करता है। मतदान के बाद जब चुनाव परिणाम आते हैं। जो भी विधायक अथवा सांसद चुने जाते हैं, वह जिस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह से विजय प्राप्त करते हैं। चुनाव जीतने के बाद वह अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए जिस पार्टी से वह चुनाव जीते हैं, उसको छोड़कर अन्य राजनीतिक दल में चले जाते हैं। वर्तमान में जो दल-बदल कानून है, उसका तोड़ राजनीतिक दलों द्वारा निकाल लिया गया है। वह संख्या के आधार पर सामूहिक दल-बदल करके सरकार गिराने और बनाने का काम करने लगे हैं। इसमें दल बदलने पर करोड़ों रुपए की कमाई निर्वाचित विधायकों और सांसदों को होती है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। दल-बदल करने के बाद कई राज्यों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्री का पद मिल जाता है। इस कारण पिछले 10 वर्षों में दल-बदल की घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। दल-बदल कानून एक तरह से निष्प्रभावी होकर रह गया है। मतदाता अपने आपको ठगा हुआ महसूस करता है। जो विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, वह अपने मतदाताओं से पार्टी बदलने के ?लिये रायशुमारी भी नहीं करते हैं। एक तरह से ?निर्वा?चित प्र?तिनिधि मतदाताओं को धोखा देते हैं। मतदाता अपने अधिकार 5 वर्ष तक के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से विधायक और सांसद को देता हैं। मतदाता राजनी?तिक दल की विचारधारा और राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिनिधि चुनता है। संविधान ने मतदाता को प्र?तिनिधि चुनने का अधिकार दिया है।

मतदाता के साथ दल-बदल धोखाधड़ी करना, यह एक तरह का अपराध है। 91 के संविधान संशोधन में 2003 में इसमें संशोधन किया गया। दो तिहाई सदस्यों के विलय करने पर ही दल-बदल को सही ठहराया गया। इस संशोधन में एक संशोधन यह भी था, एक तिहाई सदस्य यदि अपनी पार्टी से अलग होकर अलग गुट बना लेते हैं, तो उसे दल-बदल नहीं माना जाएगा। पिछले 10 वर्षों में इस प्रावधान का जबरदस्त दुरूपयोग हुआ है। अलग गुट बनाकर गठबंधन की सरकार में शामिल होकर सरकारों को गिराने और बनाने का खेल शुरू हो गया है! वर्तमान दल-बदल और खरीद बिक्री की स्थिति को देखते हुए दल-बदल कानून में परिवर्तन किए जाने की मांग बड़ी तेजी के साथ उठने लगी है! कहा जा रहा है, कि जनप्रतिनिधि को जिस पार्टी से वह चुना गया है यदि वह पार्टी छोड़ना चाहता है, तो पहले वह अपने विधायक और सांसद के पद से इस्तीफा दे। उसके बाद चुनाव लड़कर वह जहां जाना चाहता वहां जाए है। निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी छोड़कर निर्दलीय या जिस पार्टी में जाना चाहता है, उसकी टिकट पर चुनाव लड़कर मतदाताओं का विश्वास जीते। सांसद हो या विधायक, वह मतदाताओं का प्रतिनिधित्व विधानसभा अथवा लोकसभा में करता है। संविधान के अनुसार मतदाता ही सर्वोपरि है। मतदाताओं के दिए गए अधिकार का दुरुपयोग करना निर्वाचित प्रतिनिधि का अधिकार नहीं हो सकता है। जिस तरह से निर्वाचित प्रतिनिधि अभी दल-बदल कर हॉर्स ट्रेडिंग की तरह खरीदे और बेचे जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तभी लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। जन प्रतिनिधियों को तभी मतदाताओं के प्रति उत्तरदाई बनाया जा सकता है।

दक्षिणा की युक्ति और बॉन्ड से मुक्ति

देश के चुनावी बॉन्ड पर बवाल मचा हुआ है। ये सब फालतू का तमाशा हो रहा है। ऐसे सब मसलों का समाधान पहले से मौजूद है। ईसाई धर्म में आप चुपके से जाकर कन्फेशन कर लेते हैं और पादरी हल निकाल लेते हैं। पर हिंदुओं में तो सार्वजनिक पाप निवारण की व्यवस्था है।

हमारे देश में लोग पवित्र नदियों में अपने पापों को भी गंगा में बहाकर मुक्ति पाने का वरदान पाते हैं। किसी ने कोई भी पाप किया हो तो इसकी पूरी व्यवस्था है जिससे पाप का निराकरण संभव है। गंगा मइया के घाटों पर बैठे पंडे पुजारी सारी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अपनी फीस वसूलते हैं। पाप करने वाले को भी अपना घर पालना है और पाप के निराकरण के सारथी पंडे पुजारी को भी।

अब पंडे पुजारियों के रोजगार पर डाका पड़ने वाला है, बल्कि पड़ना चालू हो गया है। एकदम नये आधुनिक तरीके और नये नियम कानून बन गये हैं। पंडे पुजारियों की एक गुप्त बैठक में ये चिंता जाहिर की गई कि पापों के निराकरण का काम हमारा था अब ये काम किसी बॉन्ड को दे दिया गया है। 'ये तो हमारा अपमान है। बेरोजगारी के इस समय में हमारे रोजगार पर लात मारी जा रही है।' सारा काम पोथी पत्रों से करने के खिलाफ मुहिम चलाने वाले एक पढ़े-लिखे पंडे ने कहा कि हम कब से अपने काम को आधुनिक करने की अपील कर रहे हैं पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इस मशीनीकरण ने ही हमारी जिंदगी मुश्किल कर रखी है। हमारी सदियों पुरानी परम्परा और तौर-तरीके ऐसे ही कंप्यूटर से बर्बाद हो रहे हैं।

एक पंडा बोला, 'ये तो बताओ मामला क्या है?' गुस्से में तमतमाये हुए एक पंडे ने कहा कि जो काम सदियों से, पीढ़ियों से हम करते आए हैं वो काम अब कोई बॉन्ड कर रहा है। लोगों के पापों का निराकरण अब बॉन्ड करेगा और हम देखते रहेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। फिर भी दुस्साहस करके किसी ने पूछ लिया कि ये तो कोई विदेशी नाम मालूम पड़ता है तो कोई विदेशी कंपनी आ गयी है क्या? कितनी दक्षिणा मिली उसे? सवालों की बौछार-सी हो रही थी। जवाब कम पता थे पर बहुत जरूरी बात का पता लगा लिया गया था कि सोलह-सत्रह हजार करोड़ की दक्षिणा का मामला है।

बहुतों ने हैरानी और उत्साह में कहा कि इतनी बड़ी दक्षिणा तो कोई खास ही मामला होगा! कोई इतना बड़ा भी पाप हो सकता है जिसकी इतनी बड़ी दक्षिणा दे रहा है? जो इतनी बड़ी दक्षिणा दे रहा है उसने कितनी मोटी कमाई की होगी ये तो हम अपने अनुभवों से जानते ही हैं! सभी के मन में लड्डू फूटने लगे। तभी किसी होनहार पंडे ने सभी को फटकार लगाई कि अभी दावतों का नहीं बल्कि दक्षिणा की लूट का प्रश्न है। मामले का हर पहलू पता लगाने की जरूरत है।

खैर, मीटिंग खत्म हुई कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, समय आने पर बोलेंगे, तब तक बॉन्ड की जानकारियां जुटाने का काम उसी पढ़े-लिखे को दे दिया गया है। सभी घाट पर अपने-अपने जजमानों के पापों के निराकरण के लिए निकल गये।

लेखक :- नरेश प्रेरणा

प्रतिकूल वातावरण से विलुप्ति के कगार पर

योगेश कुमार गोयल

नन्ही-सी प्यारी गौरैया दो दशक पहले तक हर कहीं झुंड में उड़ती देखी जाती थी लेकिन अब यह दुर्लभ पक्षी की श्रेणी में आ गई है। भारत के अलावा यूरोप के कई हिस्सों में भी इनकी संख्या काफी कम रह गई है। गौरैया को नीदरलैंड में तो 'दुर्लभ प्रजाति' की श्रेणी में रखा गया है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, चेक गणराज्य इत्यादि कुछ अन्य देशों में भी गौरैया की संख्या तेजी से घट रही है। पश्चिमी देशों में इनकी आबादी घटकर खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है।

दुनियाभर में गौरैया की कुल 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से पांच भारत में मिलती हैं। ब्रिटेन की 'रॉयल सोसायटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स' ने भारत सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में अध्ययनों के आधार पर गौरैया को 'रेड लिस्ट' में डाला है। 'रेड लिस्ट' में उन जीव-जंतुओं या पक्षियों को डाला जाता है, जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में गौरैया की कुल छह प्रजातियां हाउस स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो, डैड सी अथवा अफगान स्क्रब स्पैरो, ट्री स्पैरो अथवा यूरेशियन स्पैरो, सिंध स्पैरो तथा रसेट अथवा सिनेमन स्पैरो पाई जाती हैं। भारत में गौरैया की आबादी में 60 फीसदी के आसपास कमी आई है।

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के सर्वेक्षण के अनुसार गौरैया की संख्या आंध्र प्रदेश में करीब 80 फीसदी तथा केरल, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में 20 फीसदी तक कम हो चुकी है। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों में इनकी संख्या 70 से 80 फीसदी तक कम होने का अनुमान है।

पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर गौरैया के संरक्षण के लिए समय रहते ठोस प्रयास नहीं किए गए तो संभव है कि नन्ही-सी चिड़िया गौरैया इतिहास का प्राणी बनकर रह जाए। दरअसल, हमने धरती, जल, वायु प्रकृति के इन सभी तत्वों को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि इसका दुष्प्रभाव अब मनुष्य के अलावा धरती पर विद्यमान तमाम जीव-जंतुओं और पशु-पक्षियों को भुगतना पड़ रहा है। गौरैया की तेजी से घटती संख्या को देखते हुए गौरैया के अलावा शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के संरक्षण के प्रति भी जागरूकता लाने के उद्देश्य से वर्ष 2010 से प्रतिवर्ष 20 मार्च को 'विश्व गौरैया दिवस' मनाया जाता है।

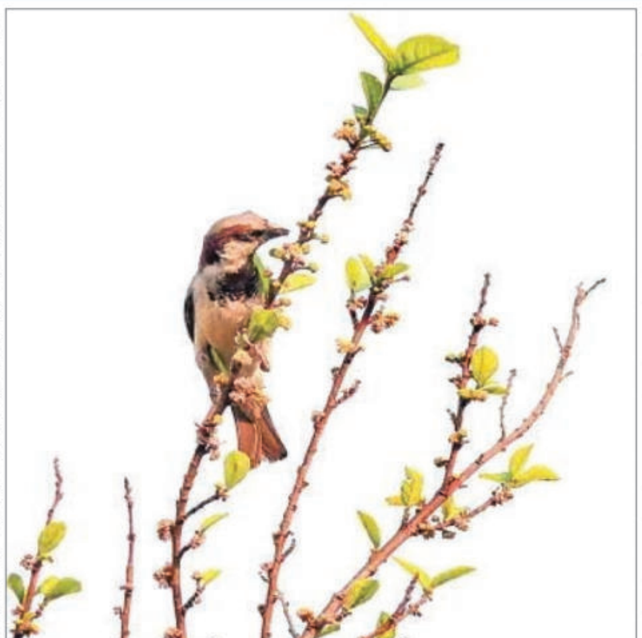

गौरैया की तेजी से घटती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा इसे वर्ष 2012 में राज्य-पक्षी घोषित कर दिया गया था, बिहार का भी यह राजकीय पक्षी है। अपने निहित स्वार्थों के चलते हमने जंगल उजाड़ दिए। वहीं प्रकृति का संतुलन चक्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे जीव-जंतुओं और पक्षियों की अनेक प्रजातियों को मारकर, उनका शिकार करके या उनके आशियाने उजाड़कर उनके अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। गौरैया की चहचहाहट अब कहीं गायब हो गई है।

भोजन तथा पानी की कमी, पक्के मकान बनने से घोसलों के लिए उचित स्थानों की कमी, तेजी से कटते पेड़-पौधे, हमारी बदलती जीवनशैली, मोबाइल रेडिएशन का दुष्प्रभाव, तापमान में लगातार होती बढ़ोतरी इत्यादि कई ऐसे प्रमुख कारण हैं, जो गौरैया की विलुप्ति का कारण बन रहे हैं। खेतों में कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से भी इनके अस्तित्व पर काफी बुरा असर पड़ रहा है।

पर्यावरणविदों के मुताबिक गौरेया काकून, बाजरा, धान, पके हुए चावल के दाने इत्यादि खाती है। किन्तु अत्याधुनिक शहरीकरण के कारण उसके प्राकृतिक भोजन के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, उनके आशियाने उजड़ रहे हैं। नये जमाने के बन रहे घरों में गौरैया के घोसले बनाने की जगह ही नहीं रही है। अब ग्रामीण इलाकों में भी घर बनाने के तरीके बदल गए हैं। अब शहर हों या गांव, हर कहीं मोबाइल फोन के लिए बड़े-बड़े टॉवर लगे हैं। इन टावरों से निकलने वाला रेडिएशन गोरैया की लगातार घटती संख्या का बड़ा जिम्मेदार कारण है। दरअसल, इन टावरों से निकलने वाली इलेक्ट्रो मैग्नेटिक किरणें इस छोटे से पक्षी को उत्तेजित करती हैं, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता बहुत कम हो जाती है और वह दिशाभ्रम की शिकार भी होती है।

पर्यावरणविदों के अनुसार गौरैया अधिकांशतः छोटे-छोटे झाड़ीनुमा झुरमुट वाले वृक्षों पर रहती हैं लेकिन विकास की अंधी दौड़ में गौरैया सहित अन्य पक्षियों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। लोग अपने घरों में गौरैया के घोसले को बसने से पहले ही उजाड़ देते हैं। पक्षी विज्ञानी कहते हैं कि गौरैया को फिर से बुलाने के लिए लोगों को अपने घरों में कुछ ऐसे स्थान उपलब्ध कराने चाहिए, जहां वे आसानी से घोसले बना सकें। ताकि वे इन घोसलों में उनके अंडे तथा बच्चे हमलावर पक्षियों से सुरक्षित रह सकें। प्रकृति संतुलन तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आज समय की सबसे बड़ी मांग है कि हम पक्षियों के लिए वातावरण को उनके प्रति अनुकूल बनाने में सहायक बनें।

बहरहाल, प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में हमारी सहभागी रही गौरैया के संरक्षण के लिए लोगों में बड़े स्तर पर जागरूकता पैदा किए जाने की सख्त जरूरत है।

गांधी सागर अभयारण्य में अफ्रीका से ठंड में लाए जाएंगे चीते

माही की गूंज, मंदसौर।
साहिल अगवान

मंदसौर जिले के गांधीसागर अभयारण्य में अफ्रीका से आने वाले चीते अब अगली ठंड तक ही आएंगे। पहले लोकसभा चुनाव के चलते यह प्रोजेक्ट टाला गया था और अब शाजापुर से काले हिरण लाने का प्रोजेक्ट बारिश के बाद तक के लिए टल सकता है।

चीतों के भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए शाजापुर जिले से 400 काले हिरण पकड़कर लाने थे, लेकिन पहले हेलीकॉप्टर के टेंडर में तकनीकी गड़बड़ी से अनुबंध नहीं हो पाया और अब गर्मी शुरू होने से अफ्रीका की टीम ने हिरण पकड़ने से इनकार कर दिया है।

अफ्रीकी टीम के अनुसार गर्मी में शिफि्टंग के दौरान परेशानी हो सकती है। अब ठंड में हिरण पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा। गांधीसागर में निरीक्षण के लिए भी अब तक टीम नहीं पहुंची। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है, जिससे चीतों को लाने का अभियान नवंबर-दिसंबर तक टल सकता है। हालांकि अधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं।

स्थानीय वन विभाग की तैयारियां पूरी

गांधीसागर अभयारण्य के रामपुरा पठार क्षेत्र में चीतों को बसाने के लिए स्थानीय वन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। चीतों को बसाने के लिए गांधीसागर में बाड़ा भी लगभग तैयार हो चुका है। 8 हजार 900 हेक्टेयर में बाड़ा बना दिया है। जंगल व बाड़ा क्षेत्र में चीतों के शिकार के लिए वन विभाग शाजापुर से 750 एवं वन विहार से 200 चीतल लाने के प्रयास में जुट गए है।

350 चीतल छोड़े जा चुके

गांधीसागर में अब तक नरसिंहगढ़ सेंचुरी से लाए गए 350 से अधिक चीतल छोड़े जा चुके हैं। चीते के शिकार के लिए हिरण शाजापुर से लाना है। शाजापुर जिले में किसान काले व सामान्य हिरण से परेशान है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अफ्रीका वाइल्ड लाइफ एंड कंजरवेड साल्यूशन कंपनी को शाजापुर हिरण पकड़ने का काम दिया यह कंपनी वन्य जीवों को पकड़ने का कार्य करती है।

कलेक्टर ने दिए पेट्रोल-डीजल पम्पों पर रिजर्व स्टाक रखने के निर्देश

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश बाथम द्वारा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को उनके पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल एक हजार लीटर एवं डीजल दो हजार लीटर पम्पेबल रिजर्व स्टाक सुरक्षित रखने तथा पेट्रोल, डीजल की पम्पों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने हेतु आदेश जारी किए गए हैं। पम्प संचालक रिजर्व स्टाक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की स्वीकृति से ही डीजल, पेट्रोल का प्रदाय कर सकेंगे। आदेश उल्लंघन की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

प्लास्टिक, कांच बोतल अथवा केन में नहीं मिलेगा पेट्रोल

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आदेश जारी किया गया है कि, जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पम्प किसी भी उपभोक्ता को कांच बोतल अथवा प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त आशय का फ्लेक्स, पेट्रोल पम्प संचालक अपने पेट्रोल पम्प पर सहज दृश्य स्थल पर लगाएं। यदि किसी पेट्रोल पम्प संचालक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है या पम्प की जांच के समय पम्प संचालक कांच अथवा प्लास्टिक की बोतल, केन में पेट्रोल का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुनि संघ के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हुआ शुभारंभ

माही की गूंज, मंदसौर।

श्री दिगंबर जैन महावीर जिनालय जनकुपुरा में 10 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हो चुका है। परम पूज्य मुनि प्रशांत सागर, साध्य सागर, संयत सागर व मुनि शीलसागर महाराज के सानिध्य में अशोक कुमार अभय कुमार अजमेरा परिवार द्वारा आयोजित मंडल विधानकी घट यात्रा जनकुपुरा महाजन मोहल्ला से प्रारंभ हुई, जो धान मंडी बड़ा चौक, गणपति चौक, होते हुए महावीर जिनालय पर संपन्न हुई, यहां पंडित अरविंद जैन व आनंद जैन शास्त्री के द्वारा मांगलिक क्रियाएं करवाई गई।

समाज रत्न शांतिलाल बड़जातियां व डॉ. मनसुख लाल गांधी द्वारा मन्त्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज के नव मनोनीत अध्यक्ष अजय कुमार बाकलीवाल व श्रावक श्रेष्ठ विजेंद्र कुमार सेठी ने अखंड दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया। डॉ. चंदा भरत कोठारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, इंद्र प्रतिष्ठा मंडप प्रतिष्ठा अभिषेक शांतिधारा सकलीकरण आदि समस्त क्रियाएं पूजन कर्ताओं द्वारा संपन्न की गई।

नरवाई जलाना प्रतिबंधित

माही की गूंज, रतलाम।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेश बाथम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जिले में नरवाई जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। उक्त आदेश जिले में लोक प्रशांति कायम रखना, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, किसी भी अप्रिय स्थिति तथा जन धन की हानि की रोकथाम के उद्देश्य से आगामी दो माह की अवधि हेतु जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि, रतलाम जिले की सीमा में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेत में फसल कटाई के पश्चात खेत की साफ सफाई एवं खापे (नरवाई) को नष्ट करने के उद्देश्य से उनमें आग जलाकर उन्हें नष्ट नहीं करेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि, जिला दंडाधिकारी को अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सभी ग्रामों में रबी की फसल कटाई का कार्य चल रहा है। किसानों द्वारा हार्वेस्टर मशीनों से फसल काटने के बाद खेत में खड़े खापे (नरवाई) को नष्ट करने के लिए तथा खेत की साफ सफाई के लिए खेतों में आग लगाई जाती है। जो वायु प्रदूषण का कारण है तथा जिसके कारण पास के खेतों में खड़ी फसलों के जलकर नष्ट होने की घटनाएं होती रहती हैं। कृषकों में आए दिन विवाद भी होते रहते हैं जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका भी बनी रहती है। अतः उपरोक्त प्रकार की घटनाओं की रोकथाम तथा लोक प्रशांति कायम करने की दृष्टि से जिला दंड आअधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

मतदान करने की दिलाई शपथ

माही की गूंज, मंदसौर।

मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शामगढ़ में वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 7 मे होली के रंग के द्वारा मतदाता को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चेना खाती, विमल कोर, नसीम बानो, सुनीता सोनी, मुमताज बी, कल्पना चौधरी, अंजला डायस एवं वार्ड की महिलाए उपस्थित रही। महिलाओ से आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान अवश्य करने हेतु समझाइश दी गई एवं फागोत्सव अंतर्गत जिस तरह अलग-अलग रंगो से होली खेलकर भी यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार सभी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक अगर मिलकर मतदान करेंगे तो एक अच्छी सरकार चुनने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु नारे लगवाए गए एवं मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई।

जनप्रतिनिधियों के नामपट्टिकाओं को ढंकने पर रोक लगाने की मांग

माही की गूंज, मंदसौर।

भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मंदसौर नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों की नामपट्टिकाओं को ढंकने की कार्यवाही को तत्काल रोकने की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत में कहा कि, मंदसौर नगरपालिका से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए जनता प्रतिदिन अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने के लिए नगरपालिका भवन में आते हैं। किंतु जनप्रतिनिधियों की नामपट्टिकाओं के ढंके होने के कारण जनता में संशय की स्थिति उत्पन्न होती है कि किस कक्ष में कौन सा जनप्रतिनिधि उपलब्ध है। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से जनता की असुविधा को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर को नामपट्टिकाओं को ढंकने की कार्यवाही तत्काल बंद करने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल एवं न्यायिक व निर्वाचन विभाग के सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा उपस्थित रहे।

शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले जाने पर आरोपित को 20 वर्ष की सजा

माही की गूंज, शाजापुर।

शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपित विनोद पुत्र रामचरण निवासी ग्राम मोहना थाना मोहन बड़ोदिया को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा में 20 वर्ष का कारावास एवं तीन हजार के अर्थदण्ड, भादवि की धारा 363 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 366 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रतीक श्रीवास्तव एडीपीओ शाजापुर से मिली जानकारी अनुसार 29 दिसंबर 2022 को पीड़ित बालिका के पिता ने थाने पर सूचना दी की उसकी लड़की जो कक्षा 11वीं में पढती है वह 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे मौसी के घर मिलने का जाने का बोलकर घर से गई थी जो शाम तक घर वापस नहीं आई, परिवार में तलाश करने पर कोई पता नहीं चला।

पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की गई। विवेचना के दौरान साक्षियों से पता चला कि विनोद उसे ले गया होगा। पुलिस ने पीड़िता को विनोद के कब्जे से पकड़ा। पीड़िता ने बताया कि वह चार वर्षो से विनोद को पहचानती है , विनोद से उसकी बातचीत होती थी, विनोद उसे शादी का झांसा देकर इंदौर व फिर मोरबी लेकर गया। उन्होने मंदिर में शादी कर ली और मोरबी में ही एक कमरे में रहकर कई बार शारीरिक संबंध बनाये। पीड़िता 18 वर्ष से कम थी इसलिए पास्को एक्ट एवं भादवि की अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया।

नवागत थाना प्रभारी ने संभाली थाना कोतवाली की कमान

माही की गूंज, मंदसौर।

चुनावी सीजन में तबादलों के बीच मंदसौर कोतवाली थाने में नये थाना प्रभारी पुष्पेन्द्रसिंह राठौर ने कमान संभाल ली है। राठौर वैसे तो नीमच जिले से स्थानांतरित होकर मंदसौर आये हैं, लेकिन नीमच में वे 15 दिन ही रहे और उनका तबादला मंदसौर हो गया।इससे पहले वे कुबेर धाम की नगरी सिहोर जिले के आष्टा में पदस्थ थे।

थाना प्रभारी राठौर ने चर्चा में बताया कि, वे महादेव के भक्त हैं और महाकांल की नगरी उज्जैन के मूल निवासी हैं। अब बाबा की ही कृपा से पशुपतिनाथ की नगरी में आने का अवसर मिला है यहां भी पूरी लगन और निष्ठा से काम करेंगे। अपराधों पर नियंत्रण रखना और आमजनों में पुलिस के विश्वास को कायम रखा जायेगा, अपराध करने वालों या लॉ एंड आर्डर बिगाडने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।

राठौर ने अपने बारे में बताया कि, वे वर्ष 2010 में उपनिरीक्षक के तौर पर पुलिस सेवा में आये और मुरैना में चार वर्ष, दो वर्ष बालाघाट में चार वर्ष खण्डवा में व तीन वर्ष सिहोर जिले के विभिन्न थानों पर पदस्थ रहे हैं। अब वे पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में आये हैं और कोतवाली थाने की कमान संभाल रहे हैं।

आत्महत्या कांड के फरियादियों ने की आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग

माही की गूंज, मंदसौर।

विगत दिनों मंदसौर जिले के ग्राम रूण्डी में दिल दहला देने वाला मामला हुआ था, जिसमें गांव के रहने वाले प्रकाश बंजारा (35) ने अपनी बेटी सुमन (13) और बेटे विशाल (10) को पेड़ पर फंदा डालकर फांसी लगा दी थी और खुद भी फंदे पर झूल गया था।इस मामले में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के मकान गिराने की मांग को कलेक्टर को ज्ञापन दिया है।

आत्महत्या के इस मामले में पुलिस ने राजू राठौर, कालू, सोनू, गोविंद, लीलाबाई, नोजीबाई और गीताबाई सभी निवासी रुंडी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। मृतक की पत्नी नैनीबाई, मां सीताबाई, पिता सूरजमल बंजारा, वकील बंजारा ने बताया कि पहले प्रशासन ने तीन दिन में मकान को तोडने का आश्वासन दिया था उसके बाद 17 मार्च तक आरोपियों के मकान तोडने की कहा था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब प्रशासन कह रहा है कि मकान में सामान रखा है, उसका कौन जिम्मेदार होगा। इस प्रकार बहाने बाजी

की जा रही है। इसलिए हम फिर से कलेक्टर मंदसौर से मिलने आये हैं और उन्हें ज्ञापन सौंप न्याय की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हमें लगता है कि कलेक्टर भी आरोपियों के दबाव में कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

मृतक की पत्नी नैनी बाई ने बताया कि, मेरे पति और बच्चों की अस्थियां अब तक श्मशान घाट में ही हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम उन्हें नहीं उठायेंगे। न्याय की गुहार लगाने आज फिर हम मंदसौर कलेक्टर के पास आये हैं।

मृतक के परिजनों ने बताया कि, आरोपियों में अभी भी कानून या पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जेल के अंदर से भी वे हमारे पास धमकियों भरें संदेश पहुंचा रहे हैं। हम लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। हमारी मांग यह है कि आरोपियों के अवैध मकानों को जल्द से जल्द तोडा जाये।

नैनीबाई ने ज्ञापन में कहा कि, यदि आरोपियों के मकानों को नहीं तोडा जाता है तो वह भी कलेक्टर कार्यालय के सामने आत्महत्या कर लेंगी और उसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

मार्च में बढ़ने लगा पारा, दिन में तेज धूप का असर

माही की गूंज, बड़वानी।

मार्च में फागुन का रंग चढ़ने के साथ ही गर्मी का रंग भी असर दिखने लगा है। दिन और रात के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में लोगों के घरों में पंखों के साथ अब कूलर चालू हो चुके हैं। खास बात ये है कि, पिछले कुछ दिनों से चिलचिलाती धूप निकल रही है। जिससे बाहर निकलने पर गर्मी का एहसास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है।

चिकित्सकों ने दी सलाह

उधर, गर्मी शुरू होते ही मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ठंड के मौसम की विदाई और गर्मी की शुरूआत हो रही है। इससे बीमारियां बढ़ने लगती है। इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत होती है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में तेज गर्मी पड़ने लगेगी और तब लू, टायफाइड, फूड प्वाइजनिग, डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और अनुचित खानपान से परहेज करना चाहिए।

तपने लगे पहाड़ी क्षेत्र, गर्म हवाएं चलने लगी

कई दशक पूर्व तक क्षेत्र के सतपुड़ा के पहाड़ी हरियाली के लिए प्रसिद्ध थे, अब पहाड़ी क्षेत्र से हरियाली गायब हो चुकी है। बिगड़े वनों के सुधार कार्यक्रम के तहत जरूर पौधारोपण हुआ था, लेकिन क्षेत्र के पहाड़ी अंचल पाटी-बोकराटा क्षेत्र में पहाड़ियां अब बिना पेड़ के कारण मार्च में ही तपने लगी है। पहाड़ी नाले-झरने सूख चुके हैं। हालांकि नहरों का जाल फैलने से पाटी क्षेत्र के कई इलाकों में सिर्फ वर्षा के समय फसल ले पाने वाले किसान अब गर्मी में भी फसल बोवनी का लाभ लेने लगे है।

पक्षियों के लिए रख रहे दाना पानी

बढ़ती गर्मी के बीच पर्यावरण एवं पक्षी प्रेमी अपने घर की छतों पर मिट्टी के सकोरों में पक्षियों के लिए दाना-पानी रख रहे हैं। ताकि गर्मी से बेहाल गौरैया और अन्य पक्षी दाना पानी लेकर अपनी भूख प्यास मिटा सकें। उनका संरक्षण हो सके। पर्यावरण व पक्षी प्रेमी केजार आदिल बोहरा ने बताया कि गर्मी के दिनों में हर इंसान को मूक प्राणियों के बारे में भी सोचना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनका जीवन भी सुरक्षित रह सके।

कम बारिश के कारण गिरा भूजल स्तर, बगैर अनुमति ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध

माही की गूंज, बड़वानी।

जिले में विगत वर्षों में कम बारिश होने के कारण भू-जल स्तर में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है। आगामी गर्मी में और अधिक गिरावट होने की संभावना है इसके मद्देनजर कलेक्टर ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर पानी का उपयोग पीने व निस्तार के अलावा अन्य कार्यों में करने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। जिले में गिरे हुए जलस्तर के कारण क्षेत्र के जलस्त्रोतों में भी पानी की कमी आने लगी है। नदियों की धारा छोटी होने के साथ ही मुहाने मैदान में नजर आने लगे हैं।

दरअसल, कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने मप्र पेयजल परिरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 के अंतर्गत अन्य आदेश होने तक संपूर्ण जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर जल स्त्रोतों कुएं, तालाब, नदी, हैंडपंप, ट्यूबवेल से पेयजल एवं निस्तार के लिए जल के उपयोग को छोड़कर अन्य उपयोग के लिए प्रतिबंध आदेशित किया है।

एसडीएम की लेना होगी अनुमति

बड़वानी में प्राकृतिक रूप से नर्मदा नदी को छोड़कर बहने वाली नदी-नालों तथा तालाबो में उपलब्ध पानी एवं भूमि सतह के नीचे पानी का घरेलू उपयोग एवं पशु धन के रख-रखाव के प्रयोजन के अतिरिक्त पानी की निकासी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति के बिना तथा पूर्व से स्थापित नलकूप की 150 मीटर के रेडियस में कोई भी नलकूप खनन नहीं करवा सकेगा। बिना अनुमति अवैध उत्खनन के मामलों में उक्त अधिनियम में उपबंधित नियमानुसार अपने क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्रवाई करेंगे।

ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, दर्दनाक हादसे में एक की मौत 30 से ज्यादा लोग घायल

माही की गूंज, बड़वानी।

निमाड़ अंचल में इन दिनों भोंगर्या हाट को लेकर आदिवासी समाज मे खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इन दिनों लगने वाले हाट में आदिवासी समाजजन सजधज कर हिस्सा ले रहे है ऐसे ही एक हाट आज जिले के बिजासन में लगा था जहां से वापस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार ग्रामीण अपने गाँव बोरखेड़ी जा रहे थे। इसी दौरान ग्राम नलती के पास ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर पलट गई जिसमें करीब 39 लोग घायल हो गए।

इस घटना एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए बड़वानी जिला अस्पताल लाया गया है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही बड़वानी विधायक राजन मंडलोई सहित बढ़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। मामले में एसडीओपी बड़वानी ने बताया के सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है उनके अनुसार घायलों में महिला पुरुष और बच्चे शामिल है।

रहवासी क्षेत्र की तीन मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, मुश्किल से पाया गया काबू

माही की गूंज, खरगोन। जिले में मंगलवार देर शाम रहवासी इलाके की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसा, शहर के पॉश एरिया में गिनी जाने वाली विश्वशखा कॉलोनी के एक मकान की तीसरी मंजिल में हुआ।अचानक हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया, हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।

खरगोन नगर की विश्वशखा कॉलोनी में मंगलवार देर शाम अचानक एक तीन मंजिला मकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्रवासी भी अपने घरों से बाहर आ गए। जिस बिल्डिंग में आग लगी है वह नगर के इंजीनियर सुनील निगम की रहवासी बिल्डिंग है। आग की लपटें उठते देख क्षेत्र वासियों ने बिल्डिंग में रखी गैस की टंकियों को बाहर निकाल कर फेंका, जिससे बड़ी घटना होने से रोका जा सका। सुनील निगम के मुताबिक उनकी पत्नी शाम को दीपक लगाने के बाद कॉलोनी के मंदिर गई थीं। लौटकर वापस आईं तो उनका घर आग की चपेट में आ चुका था। सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम में समय रहते आग पर काबू पाया जिससे बड़ा हादसा टल गया।

बेटी की चीख–पुकार सुन उड़े पिता के होश, एक झटके में लगा हजारों का चूना

माही की गूंज, खरगोन।

जिले में साइबर क्राइम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से वाइस क्लोन के जरिए खरगोन के एक पेट्रोल पंप संचालक श्याम भंडारी को उसकी इन्दौर में पढ़ रही बेटी को एक गंभीर मामले में दो सहलियों के साथ सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करने का डर बताते हुए धमकाया गया।

वहीं इस मामले को रफा-दफा करने के नाम पर रूपए भी मांगे गए। इस दौरान व्यापार से जुड़ा पूरा प्रतिष्ठित परिवार डरा हुआ है। खास बात यह है की साइबर क्राइम के नाम पर शातिर बदमाशों ने इस दौरान बेटी की माता ममता और पिता श्याम भंडारी दोनों से करीब ढाई घन्टे तक व्हाट्सएप कालिंग पर बात की।

सीबीआई के नाम पर की पैसों की मांग

यही नहीं इस दौरान वाइस कॉल के जरिए बेटी की चिखने की आवाज भी सुना दी। बेटी का मोबाइल बंद आने पर परिवार ने 50 हजार रूपये ऑन लाइन ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन बदमाश यहीं नहीं रूके उन्होंने सीबीआई के नाम पर और भी पैसे मांगते रहे। लेकिन दोबारा पैसा मांगने से भंडारी परिवार को धोखाधडी की आशंका हुई। रूपये नहीं डाले और रिश्तेदारो को हॉस्टल भेजकर बेटी की जानकारी लेने भेजा गया। जिसके बाद इस सायबर क्राइम का खुलासा हुआ।

घटना के बाद भंडारी परिवार के द्वारा इन्दौर क्राइम ब्रांच को की गई शिकायत के बाद इन्दौर क्राइम पुलिस हरकत में आ गई है। जिसके बाद वाइस कॉल के माध्यम से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इधर इस गंभीर मामले के बाद परिजन और रिश्तेदार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम से अब सतर्क रहे। वाइस कॉल के मामले से समाज में चिंता बढ़ गई है। बिना कन्फर्म किए कोई पैसा ऑन लाइन ट्रांसफर न करें।

5 बाइक के साथ 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार

माही की गूंज, अलीराजपुर।

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत कस्बा अलीराजपुर एवं आसपास के क्षेत्र में विगत समय से दो पहिया वाहन चोरी की लगातार वारदाते अज्ञात बदमाशों के द्वारा की जा रही थी, जो पुलिस के लिये लगातार चुनौती बना हुआ था। अज्ञात वाहन चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर के द्वारा अनुविभागीय अधिकरी पुलिस अलीराजपुर अश्विनी कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शिवराम के अधीनस्थ थाना कोतवाली की अलग-अलग टीमें अज्ञात वाहन चोर गिरोह के धरपकड हेतु बनाई गई थी। पुलिस टीमें थाना प्रभारी निरीक्षक शिवराम तरोले के निर्देशन में गंभीरता से अज्ञात वाहन चोरी के आरोपियों की धरपकड हेतु मुखबीर लगाकर कार्यवाही कर रही थी।जिसके परिणामस्वरूप पुलिस टीम को अज्ञात वाहन चोरी के आरोपियों के बारे मे पता चला, जिस पर मुखबीर की सूचना पर कुल 4 आरोपियों के गिरोह को गिरफतार करनें में कोतवाली पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस टीम के द्वारा बोहरा कब्रस्तान, तालाब फलिया, एसबीआई हाट गली, बहारपुरा एवं तिलक मार्ग राठौर गली से चोरी हुई 5 दो पहिया वाहन चोरी की वारदातों के संबंध में मुखबीर की सूचना पर लगातार संदेहियों से सूक्ष्मता से पूछताछ कर रही थी। जिसके परिणामस्वरूप ही 1 संदेही को सोरवा नाके से दो पहिया वाहन चेक करते उसके पास कोई दस्तावेज होना नहीं पाये गए। जिससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चुराई गई मोसा चलाई जा रही थी। जिसकी निशानदेही पर 3 अन्य आरोपियों को गिरफतार कर कुल 5 दो पहिया वाहन बरामद वाहन बरामद करनें में सफलता पुलिस टीम को मिली है।

विगत माह में कस्बा अलीराजपुर में वाहन चोरी की वारदातों को लेकर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये गये थे। जिसमें कोतवाली पुलिस की टीमों के द्वारा 4 अज्ञात आरोपियों को ज्ञात कर, उनके कब्जे से कुल 5 दो पहिया वाहन कीमती 2 लाख रूपये के बरामद करनें मे सफलता प्राप्त की है।

धूलकोट भोंगर्या हाट बजार में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान

माजी की गूंज, खरगोन।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 20 मार्च को सेक्टर बलवाड़ा, कसरावद हाट बाजार, घुघरियाखेड़ी, सिरवेल सेक्टर, नहालदरी और धूलकोट भोंगर्या हाट बाजार में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक रहने और 13 मई को जिले का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपना योगदान देने कहा गया। इस दौरान मतदाताओं को अपने गांव, अपने शहर तथा अपने आसपास के मतदाताओं को मतदान करने व मतदान केन्द्र तक लाने के लिए प्रेरित किया गया। ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने में वंचित न रहे। हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए। मतदान भविष्य का विधाता होता है। युवा मतदाताओं को युवा पीढ़ियों को मतदान के लिए जागरूक करना चाहिए। मतदान से अपने क्षेत्र के विकास के लिए योग्य उम्मीदवार को चयनित करें। एक जिम्मेदार मतदाता ही सभी में जागरूकता ला सकता है। हमें वोट डालने का अधिकार है इसका हमें उपयोग करना चाहिए। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिससे लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके।

शिक्षक की मौजूदगी में 2 कक्षाओं के बच्चे साथ बैठकर परीक्षा हाल में कर रहे थे नकल

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन विकास खंड के एक गांव में शासकीय प्राथमिक शाला में परीक्षा के दौरान शिक्षकों की मौजूदगी में गाइड और किताब साथ रखकर परीक्षा का पर्चा हल करने का मामला सामने आया है।परीक्षा दे रहे ये यह छात्र कक्षा छठवीं और सातवीं के थे, जिन्हें एक साथ एक ही कक्षा में बैठाया गया था।

वहीं, बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी, तब वे सीधे परीक्षा कक्ष में जा पहुंचे और इस घटना का वीडियो भी बना लिया। जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चला है। हालांकि, इसकी जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच दल गठित कर इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है।

खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित खरगोन विकास खंड के ही एक गांव सुरपाला में एकीकृत प्राथमिक शाला में कक्षा छठवीं और सातवीं की परीक्षा एक मार्च को कराई जा रही थी। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों को कक्षा में छात्रों को नकल कराई जाने की जानकारी लगने पर उन्होंने सीधे परीक्षा हाल में पहुंचकर वहां का नजारा देख वे लोग दंग रह गए। दरअसल, कक्षा में बैठकर परीक्षा दे रहे छात्र गाइड और किताबें लिए परचा हल कर रहे थे। यही नहीं, कक्षा छठी और सातवीं के बच्चों को एक ही हाल में बैठाकर उनकी परीक्षा ली जा रही थी। जहां पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बच्चे टेबल पर आराम से गाइड और किताबों से देखकर पर्चा हल कर रहे थे। जब इस संबंध में ग्रामीणों ने परीक्षा ले रहे शिक्षकों से पूछताछ की तो वे कुछ जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

जांच कर दोषी पर करेंगे कड़ी कार्रवाई

इधर, इस वायरल वीडियो पर जिला शिक्षा अधिकारी एसके कानुडे का कहना है कि सुरपाला विद्यालय में परीक्षा के दौरान विज्ञान की किताब रखी थी और वीडियो भी दिखाया गया है। प्राचार्य वहां मौजूद नहीं थे। वीडियो के आधार पर प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है। अगर वो दोषी हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। टीम बनाकर जांच करेंगे। इसमें जो भी दोषी होगा, सब पर कार्रवाई करेंगे।

भगोरिया रंग में रंगे राजनीतिक दल, बजाई मांदल-थाली

आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया धूमधाम से संपन्न, कांग्रेस व भील सेना ने निकाली गैर

माही की गूंज, अलीराजपुर

पश्चिमी निमाड़, झाबुआ और अलीराजपुर में देश-विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होली से एक हफ्ते पहले से मनाए जाने वाले इस पर्व में आदिवासी अंचल उत्सव की खुमारी में डूबा रहता है। वहीं अलीराजपुर जिले के 24 स्थान पर यह मेला लगता है। जहां अलीराजपुर के आंबूआ गांव में इसकी धूम देखने को मिली। यूवा महिला पूरूष और बुजूर्गो भी चमकदार कपड़े, पारंपरिक नृत्य के साथ इसे मानते हुऐ दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस व भील सेना संगठन के लोगों इसमें मेले में अलग अंदाज में नजर आए। जहां ढोल, मांदल और थाली बजाते हुए रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए राजनेता अपनी मौज मस्ती डूबे नजर आए हैं। इसी के साथ पुलिस के द्वारा चपे-चपे पर निगरानी सीसीटीवी कैमरे वह ड्रोन कैमरे तो पुलिस सहायता केंद्र से रखी जा रही थी। जिसको लेकर कहीं महिलाओं ने भी पुलिस की व्यवस्था को लेकर प्रशंसा की।

माही की गूंज, आम्बुआ।
मयंक विश्वकर्मा

अलीराजपुर जिले की विशेष पहचान मानने वाले आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया आज आम्बुआ में धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था माकूल रही कांग्रेस तथा भील सेना द्वारा गैर निकाली गई ग्रामीणों ने झूले चकरी का मजा लिया। वही खाने-पीने खेल खिलौने आदि की जमकर बिक्री हुई।

होली पर्व एक सप्ताह तक साप्ताहिक हाट बाजार के दिन आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया जो कि रबी की फसल पक जाने की खुशी में मनाया जाता है। 19 मार्च को आम्बुआ में मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र से आदिवासी महिला पुरुष युवक-युवतियों, बच्चे भारी संख्या में भगोरिया का मजा उठाने आए। यही नहीं विदेशी दंपति जो कि फ्रांस से आया था ने भी आदिवासी तथा भारतीय संस्कृति को नजदीक से निहारा तथा आश्चर्य चकित भी हुए। भगोरिया मेले में कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम राठौर, सोनू वर्मा, अमान पठान, मुस्तफा बोहरा, सिराज, रमेश बघेल, राकेश सरपंच (कुण्ड) आदि के साथ ही भील सेना के प्रमुख शंकर सिंह बामनिया, प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल की गुबाई में महेश बामनिया, निर्भय सिंह चौहान, मगन पचाया, रमेश डावर, रंजीत सुबला, दिनेश, राजेश, खुमला चौहान ढोल मादल की थाप पर झूमते हुए गैर निकाली। भगोरिया मेले में झूलों तथा अन्य व्यवसाययों ने जमकर व्यापार किया प्रशासन स्तर अधिकारी पुलिस विभाग पंचायत आदि का सराहनीय योगदान रहा।

प्यार करने की सजाः जूते से पीटा, सिर मुंडवाया और आधी मूंछ काट दी, पेशाब भी पिलाया

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में शादीशुदा महिला को भगा कर ले जाने पर भीड़ ने युवक को ऐसी सजा दी जिसे जान कर आप दंग रह जाएंगे। युवक को सजा दिए जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि, युवक की जमकर पटाई की जा रही है। युवक को चप्पलों की माला पहनाई गई है। युवक की पिटाई उसकी प्रेमिका से भी करवाई गई है। इसके बाद जुल्म की हर इंतिहा को पार करते हुए युवक को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया गया है। अब वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

युवक आधे बाल मुंडवा दिए गए और फिर प्रेमिका के हाथों से उसे चप्पल से पिटवाया गया। इतना ही नहीं युवक की आधी मूंछ काट दी गई। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि युवक की चप्पल से पिटाई की जा रही है और उसे जूते चप्पल सर पर रखने को कहा जा रहा है। इसके साथ ही उसके मुंह में चप्पल-जूते ठूसे जा रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस भीड़ ने महिला की भी पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाने के देवली देसी गांव का है। हैवानियत की यह घटना चार दिन पुरानी है। जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है।

युवक घट्टिया थानाक्षेत्र के भीलखेड़ी गांव का रहने वाला है,ओर बंजारा समाज का है। युवक की शादीशुदा प्रेमिका महिला बंजारा समाज की है। महिला के दो बच्चे हैं। युवक महिला को राजस्थान ले गया था। इसके बाद महिला के परिवार और गांव के लोग दोनों को राजस्थान से पकड़कर भाटपचलाना ले आए। इसके बाद लोगों ने उसे पेड़ से बांध कर जूते-चप्पल की माला पहनाई और परिवार का नाम पूछ कर उसके मुंह में जूते ठूंसे।

उज्जैन ग्रामीण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नितेश भार्गव ने बताया कि, वीडियो संज्ञान में आया है। अभी कोई शिकायतकर्ता सामने नही आया है। लेकिन जिस तरह से वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके आधार पर आरोपियों का पता लगाकर उनपर कार्रवाई की जाएगी।

मिन्याखेड़ी से भगोरिया पर्व का हुआ आगाज, 35 मांदल ढोल लेकर जमकर नाचे आदिवासी

माही की गूंज, धार। विक्रमसिंह राठौर

अमझेरा थानांतर्गत आदिवासी लोक संस्कृति के भगोरिया पर्व का आगाज मंगलवार को ग्राम मिन्याखेड़ी से हुआ। जहाँ आदिवासी पारंपरिक वेषभुषा में करीब 35 मांदल-ढोल लेकर पहुंचे, जिस पर सजे-धजे युवक-युवतीयों के द्वारा जमकर नृत्य कर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। ग्राम पंचायत के द्वारा सभी मांदल ढोल टीम का स्वागत सम्मान किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से अमझेरा थाना प्रभारी रविन्द्रकुमार बारीया दलबल के साथ मौजुद रहे।

नालछा में भगोरिया हाट में हुआ विवाद

नालछा में भगोरिया के दौरान आपरसी रंजीश में चाकू-बाजी हो गई। इस चाकू-बाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दो युवक घायल हो गए। घायलों के गंभीर चोट के चलते जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद इंदौर रेफर किया गया। ग्राम गुगली के रहवासी अजय पुत्र मोरसिंह, राजेश पुत्र मुन्नालाल, राजपाल पुत्र मुकुल मंगलवार को नालछा में भगोरिया देखने गए थे। पूरे दिन भगोरिया का आंनद लेकर वे शाम को अपने घर की ओर निकले। इस बीच नालछा व सूरजकुंड के नजदीक युवकों का विवाद हो गया।

विवाद इतना बढ़ गया कि, दूसरे पक्ष के युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। इस विवाद में युवकों को चोट आई। वहीं अजय पुत्र मोरसिंह की मौके पर मौत हो गई। राजेश व राजपाल को स्वजन निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां दोनों युवकों की स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हे इंदौर रेफर किया। इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

लहसुन की रखवाली के लिए खेत में सोए किसान की हुई हत्या

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में लहसुन के फसल की देखरेख कर रहे एक किसान की हत्या कर दी गई है। बडनगर के बलोडा लक्खा गांव में किशन सिंह छावड़ा की डेड बॉडी खेत में एक खटिये पर मिली है। किशन सिंह छावड़ा भारतीय किसान संघ के स्थानीय नेता भी हैं। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने कहा, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस हत्या के पीछे की वजह जानने में लगी है। 50 वर्ष के छावड़ा खेत में सोया करते थे। यह खेत उनके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। वो इस खेत में लहसुन की फसल की देखरेख करने के लिए सोया करते थे।

पुलिस अधीक्षक ने कहा, सुबह में वो घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिवार के सदस्य खेत पर गए यहां उन्होंने देखा कि किशन सिंह छावड़ा का शव खटिया पर पड़ा है और वो खून से सना हुआ है। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में खून लगा हुआ था। किसान के सिर पर धारदार हथियार से हमला करने के निशान मौजूद थे। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दिया कि लहसुन की फसल खेत से नहीं चुराई गई होगी इस हत्या के पीछे दुश्मनी वजह हो सकती है।

कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता परमजीत सिंह ने कहा, 'बीते दो महीनों में लहसुन का दाम 40 हजार रुपया प्रति क्विंटल पहुंच गया है। काफी लंबे समय से यह 25 हजार रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा था। किसानों को उम्मीद है कि लहसुन के दाम आगे बढ़ेंगे। खराब बारिश की वजह से मंदसौर और नीमच में लहसुन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में लहसुन के दाम और बढ़ने वाले हैं और यही वजह है कि किसान लहसुन को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा कर रहे हैं।

किसान की हत्या पर राजनीति

बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, डॉक्टर मोहन यादव जी, आप राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन आपका गृह जिला है। ज्यादा अराजकता उज्जैन में ही हो रहा है, क्यों...?

हालांकि, भाजपा ने इस मामले में कहा है कि पुलिस इसे लेकर कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता, रजनीश अग्रवाल ने कहा, जीतू पटवारी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक पर ध्यान दें। किसान की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

तुम अब अच्छे नहीं लगतेः मायके से लौटने को राजी नहीं पत्नी, एसपी के पास पहुंचा लाचार पति

छतरपुर। जिले में अजब-गजब मामला सामने आया है। मायके गई पत्नी के वापस न लौटने पर पति ने एसपी ऑफिस में गुहार लगाई है। पत्नी का कहना है कि, उसके पति अब अच्छे नहीं लगते, उनके गाल चिपक गए हैं और अब वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। ससुराल से लौटने के बाद युवक ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराकर मदद मांगी है।

जिले के थाना बमनौरा में रहने वाले अमन अहिरवार ने एसपी ऑफिस पर एक शिकायती आवेदन देते हुए पुलिस अपनी बीबी बापिस दिलाए जाने को लेकर मदद मांगी है। अमन अहिरवार का कहना है कि उसकी शादी 9 वर्ष पहले सागर जिले के एक छोटे से गांव गौर झामर में रहने वाली रानू अहिरवार से हुई थी। शादी के 9 वर्ष हो गए रानू और अमान अहिरवार के दो बेटे भी हैं। अमन ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन लगभग दो महीने पहले मेरी बीबी मुझे बिना बताए अपने मायके चली गई जब मैं उसे लेने गया तो मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे भगा दिया। इतना ही नही मेरे खिलाफ झूठा आवेदन भी सागर पुलिस थाने में दिया।

अमन ने बताया, मैंने अपनी बीबी रानू से घर वापिस चलने को कहा तो उसने मना कर दिया और उसने कहा की अब वह मेरे साथ रहना नही चाहती है पूछने पर उसने बताया की अब वह मुझे पसंद नही करती है। बीवी कहती है तुम्हारे गाल पिचक गए इसी लिए अब नही रहना तुम्हारे साथ।

पिछले दो माह से अमन अहिरवार अपनी बीबी को वापस बुलाने के लिए प्रयास कर रहा है। छतरपुर से लेकर सागर तक आवेदन दे रहा है।

दिखने में थोड़ा सुंदर इस लिए अब नही रहना चाहती मेरे साथ

अमन अहिरवार का कहना है कि, रानू मुझ से दिखने में थोड़ा सुंदर है इसी लिए वह मेरे साथ नही रहना चाहती है वह अपने जीजा के बहकावे में आकर यह सब काम कर रही है अमान अहिरवार एवं उसकी पत्नी दोनो ही 8वीं तक पढ़े हैं। अमन का कहना है की उसका बड़ा बेटा पत्नी अपने साथ ले गई जबकि उसका छोटा बेटा उसके साथ है।

मैं अब भी उससे प्यार करता हूं...

अमान अहिरवार का आरोप है कि, उसे इस बात का शक है की उसकी पत्नी का उसके ही जीजा से प्रेम प्रसंग हो गया है। बावजूद, इसके मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और सब कुछ भूलकर उसके साथ रहना चाहता हूं यही वजह की मैं अपनी पत्नी के लिए दो माह से परेशान हूं। वही अमान अहिरवार एवं रानू का मामला महिला परामर्श केंद्र में चल रहा है।

कोटा में किडनैप हुई लड़की दो लड़कों के साथ दिखी

शिवपुरी।

कोटा से 18 मार्च को नीट की तैयारी कर रही एक लड़की की अपहरण की घटना सामने आई थी। छात्रा के पिता को कुछ तस्वीरें भेजी गईं जिनमें उनकी बेटी के हाथ-मुंह बंधे हुए थे। अपहरण करने वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की। अब इस केस में एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें छात्रा दो लड़के के साथ दिख रही है। फुटेज उसी दिन (18 मार्च) का है जिस दिन उसकी तस्वीरें उसके घरवालों को भेजी गई थीं। बताया जा रहा है कि लड़की को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। सीसीटीवी के आधार पर लड़की की लोकेशन के बारे में पता लगाया जा रहा है।

चेहरे पर लगे हुए थे खून...

दरअसल, एमपी के शिवपुरी के बैराड़ निवासी रघुवीर धाकड़ ने 18 मार्च की रात को कोटा के विज्ञान नगर थाने में अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रघुवीर धाकड़ एक स्कूल चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 18 मार्च को दोपहर तीन बजे मेरे मोबाइल पर बेटी की किडनैपिंग का मैसेज आया था। आरोपियों ने कुछ तस्वीरें भेजी थीं जिनमें मेरी बेटी के हाथ-पैर और मुंह बंधे हुए थे। कुछ तस्वीरों में बेटी के चेहरे पर खून भी लगे हुए थे।

30 लाख रुपए की डिमांड

लड़की की फोटो के साथ आरोपी ने मैसेज में रघुवीर धाकड़ को बताया कि, तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। साथ ही उसे जिंदा छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। आरोपी ने बैंक खाते की डिटेल भी भेजी। उसने सोमवार को पैसे भेजने का टाइम दिया था। जानकारी के मुताबिक, मैसेज देखकर युवती के पिता ने आरोपी से कुछ समय मांगा और पुलिस को फोटो और मैसेज भेजकर शिवपुरी से कोटा के लिए निकल गए।

क्या बोला बड़ा झूठ...?

इस केस को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फोन पर बात की है। उन्होंने जल्द से जल्द जांच कर लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कही है। कोटा पुलिस ने छात्रा की सूचना देने वाले को 20 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस मंगलवार सुबह करीब सवा दस बजे पिता को कोचिंग इंस्टीट्यूट लेकर गई। कोचिंग ने छात्रा के रजिस्ट्रेशन से इनकार किया है। अब तक युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह केस पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि लड़की ने जिस कोचिंग सेंटर का नाम अपने घरवालों को बताया था वहां वह पड़ती ही नहीं थी। वहीं अब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती दो लड़कों के साथ कहीं जा रही है।

निर्वाचन के दौरान अधिग्रहित वाहनों के लिये पीओएल का स्टॉक आरक्षित करने के निर्देश

माही की गूंज, धार।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए पीओएल स्टॉक आरक्षित रखे जाने एवं पीओएल की व्यवस्था के लिये जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है। इस हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस संबंध में आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार बस, मिनी बस एवं छोटे वाहनों का अधिग्रहण किया जायेगा। निर्वाचन के दौरान अधिग्रहित किये जाने वाले वाहनों के लिय पर्याप्त मात्रा में पीओएल की आवश्यकता होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने यह भी निर्देश दिए है कि, जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप मालिकों को निर्देशित करे कि उनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में पीओएल की व्यवस्था रखने के साथ ही रिजर्व स्टॉक रखा जावे, ताकि निर्वाचन के दौरान पीओएल की व्यवस्था के लिये जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नोडल अधिकारी परिवहन की उपस्थिति में समस्त पेट्रोल पंप के मालिकों की तत्काल बैठक आयोजित करें। आवश्यकता पड़ने पर जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी की जाने वाली पीओएल पर्ची पर सभी संबंधित वाहनों को तत्काल पीओएल प्रदाय किया जाए, ताकि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की रुकावट/विलंब की स्थिति न बने।

चुनाव के चलते जांच में लगी टीम पर हमला , अवैध शराब का वाहन फूंका, पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त

पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार ,कही शराब ठेकेदार और अवैध शराब सप्लायरों के बीच का मामला तो नही ?

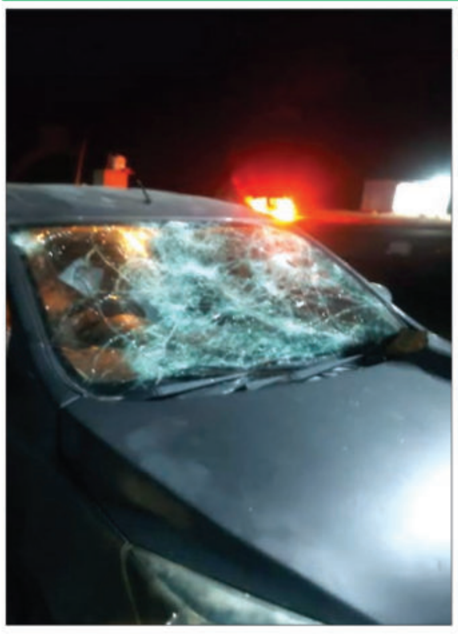

माही की गूंज़ , पेटलावद।

क्षेत्र में बढ़ते अवैध शराब सप्लाई से जुड़े माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीते 6 माह में पेटलावद विकास खण्ड क्षेत्र से पुलिस ने अलग अलग लगभग 10 चार पहिया वाहनों को अवैध शराब सप्लाई करते पकड़ा है। लेकिन सप्लायरों के हौसले इस कदर बुलन्द है कि वो इतनी कार्यवाही के बाद भी रुकने का नाम नही ले रहै। अब तो जान लेने-देने पर उतारू होकर पुलिस टीम पर हमला करने से भी नही चूक रहे।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हर जगह आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग प्वाइंट पर चेकिंग की जा रही है। रविवार रात को थांदला-बदनवार स्टेट हाइवे पर कसारबर्डी में लगे चेकिंग प्वाइंट पर जब एसएसटी टीम को जांच के दौरान मुखबिर की सूचना मिली थी। एक गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है। जब टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। यहीं नहीं उन्होंने खुद के वाहन को आग के हवाले कर पुलिस के वाहन में भी तोड़फोड़ कर डाली। रात में ही हुई इस घटना के बाद सभी पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचकर सभी हमलावरों की पहचान की गई। हालांकि आरोपी मौके से सभी फरार हो गए थे और पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर जांच की और पेटलावद थाना इलाके के ग्राम कसारबर्डी में पुलिस पर हमला कर शराब से भरे वाहन में आग लगाने वाले 8 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं।

थाना प्रभारी प्रदीप वाल्टर ने बताया कि, सोमवार को उक्त मामले में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने सभी आरोपियों को चिन्हित कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

वैध ओर अवैध के बीच का खेल तो नही ?

क्षेत्र में शराब के वाहन भर कर गाँव-गाँव मे सप्लाई करने का काम कोई नया नही है। , स्थानीय शराब ठेकेदार क्षेत्र की वेध दुकानों की आड़ में अवैध रूप से शराब सप्लाई का काम करते है जिसकी जानकारी पुलिस और आबकारी को देने पर भी कोई कार्यवाही नही होती। वही क्षेत्र में अवैध रूप से पहुँच रही अवैध शराब जिसका स्थानीय शराब ठेकेदारों से कोई लेना-देना नही होता उस पर पुलिस और आबकारी विभाग कार्यवाही कर वाहनों को पकड़ रहे है ।हमारे सूत्र बताये है कि, इन अवैध शराब वाहनों को पकड़ने की मुखबरी भी शराब ठेकेदारों के लोगो द्वारा की जाती है जिनकी सूचना और जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुँच कर अवैध शराब पकड़ने में कामयाब हो रही है। सबसे बड़ी बात वाहनों में सप्लाई की जा रही शराब किसके द्वारा दी जा रही है। ।पुलिस ने इसका खुलासा आज तक सार्वजनिक नही किया न ही पकड़े गए वाहनों के लिए किनको किस आधार पर आरोपी बनाया गया इसकी जानकारी तक नही दी गई।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए खुलेआम चल रहे ओवर लोड वाहन

आरटीओ, पुलिस और ट्राफिक पुलिस सिर्फ गरीबों पर करती है चालानी कार्रवाई

माही की गूंज़, मेघनगर।

कहते हैं कानून सभी के लिए समान होता है लेकिन यह बात अब सिर्फ किताबों तक सीमित होकर रह गई हैं। दरअसल अब कानून मकड़ी का वो जाला बन चुका है जिसे बड़े जानवर तो फाड़ कर निकल जाते है मगर छोटे उसमें फस जाते हैं। ऐसा ही आज-कल पुरे झाबुआ जिले सहित झाबुआ जिले के मेघनगर में चल रहा हैं। यहां मोटरयान अधिनियम 1988 दो तरफ से काम करता है। गरीब ,पिछड़े और आदिवासियों के लिए अलग तरह से और धन्नासेठों के लिए अलग तरह से। इस बात को कुछ इस तरह देखा जा सकता है की एक और जहां जगज-जगह पूरे जिले में पुलिस कर्मी सामान्य लोगों के वाहनों को नंबर प्लेट,हेलमेट आदि के लिए रोक कर उनका चालान बना रहे होते है। तो उसी वक्त उन्ही की आंखों के सामने से पूरे जिले में प्रदीप बस,राज बसआदि धन्नासेठों की ओवर लोड बसें निधारित सवारियों से अधिक भरकर निकल जाती है। वही मेघनगर में भी मेगनीज के ओवर लोड डंफर,गेहूं के ओवर लोड ट्रक ,खाद की ओवर लोड ट्रके,रेलवे ट्रैक से कोयला की गाडियां ,इंडस्ट्रियल एरिया से रॉक फास्फेट की ट्रके, सब खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के

परमजीत भसीन और यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए ओवर लोड पर प्रतिबंध के आदेश की अवहेलना करते हुए सरपट दौड़ रही है। जो ना सिर्फ सड़को को छतिग्रस्त कर रही बल्कि कई बार ये ओवर लोड वाहन सड़को पर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते है।.कुछ समय पहले कोयला से भरी एक गाड़ी भी साई चौराहे पर पलटने से बची थी जिस से गंभीर जनहानि हो सकती थी। मगर इन सबके बावजूद इन पर ना जिला परिवहन अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई कर रही है ना ही पुलिस कर रही है ना ही ट्राफिक विभाग कर रहा है। जिसका सीधा सा मतलब की इन धन्नासेठो की जिला परिवहन अधिकारी पुलिस और ट्राफिक विभाग से तगड़ी साठगांठ है जिस से यह लोग खुलेंआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना अधिकारियों के सरंक्षण पर कर रहे हैं और अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का किस कदर धरातल पर मजाक बना रखा है इस से ये भी समझा जा सकता है।

यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश...

दरसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2005 में परम जीत भसीन, विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट आदेश दिया था की मोटरयान अधिनियम की धारा 113 में राज्य सरकार को वजन निर्धारित करने को शक्ति है और धारा 114 के अंतर्गत राज्य सरकार के किसी अधिकारी के पास वाहन का वजन कराने की शक्ति प्राप्त है और वाहन ओवर लोड पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194 के अंतर्गत जुर्माना जो की 20000 तक धारा 200 के अंतर्गत ऑन द स्पॉट करके अंतर्गत अतिरिक्त वजन भी स्पॉट पर उतारा जाना चाहिए। मगर ना तो कानून का पालन हो रहा है ना उसकी धाराओं का ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो यह तो सीधा-सीधा जिम्मेदार अधिकारियों पर कटेंप्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का मामला है।

पंचायत से लेकर विधानसभा और अब लोकसभा का चुनाव करवाएंगे वर्षो से जमे अधिकारी

नियम कानून सब खूंटी पर वर्षो से जमे अधिकारी आखिर क्यों नही हटाये गए , विधानसभा चुनावों से चल रही शिकायत

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

देश की निर्वाचन शाखा ओर प्रणाली पर आमजन सबसे ज्यादा विश्वास रखता है और हमेशा उम्मीद रहती है कि देश मे होने वाला हर चुनाव निष्पक्ष और साफ हो जिससे जनता को सही चुना हुआ प्रतिनिधि मिल सके। निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हुए है जिसको चुनाव के पूर्व शासकीय मशनरी के माध्यम से लागू करवाया जाता है। चुनाव से पूर्व वर्षो से एक स्थान या एक जिले में जमे अधिकारीयो और स्थानीय स्तर पर पदस्थ अधिकारीयो को हटाये जाने के निर्वाचन के सख्त निर्देश है लेकिन लगातार साख खोता निर्वाचन आयोग शायद इस ओर कोई ध्यान नही देता है। जबकि विधानसभा चुनाव में हुई लापरवाही की शिकायत मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली की टेबल तक पहुँच चुकी है और भोपाल से लेकर दिल्ली तक अधिकारी इसका निराकरण नही कर पाए है। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा लापरवाही करते हुए जिले से ऐसे अधिकारीयो का तबादला नही किया जिनका तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ है। जिले में कई अधिकारी तो ऐसे भी है जो न केवल जिले में बल्कि खुद के ग्रह क्षेत्र में ही वर्षो से जमे हुए है ।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

लबें समय से जमे हुए अधिकारी, कर्मचारी करवाएंगे लोकसभा का चुनाव भी

लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व स्थानीय चुनाव हुए है। इसके बाद विधानसभा के चुनाव हो चुके है। इन चुनावों के दौरान जो अधिकारी पदस्थ थे लगभग वही अधिकारी आज भी क्षेत्र में पदस्थ है। जिंसमे से बमुश्किल कुछेक का केवल विकास खण्ड बदला गया है। चुनाव के दौरान अधिकारीयो के तबादलों को लेकर बने नियमो को ताक में रख कर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है या फिर जानकारी के नाम पर स्थानीय प्रशासन आयोग को सही और समय पर जानकारी नही भेज रहा है जिसके चलते बड़ी लापरवाही सामने आ रही है ।

आरटीआई में हो चुका है खुलासा

विधानसभा चुनावो के बाद आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण मालवीय द्वारा निर्वाचन अधिकारी भोपाल से चुनाव व्यवस्था में स्थानांतरित किये गए अधिकारी की प्रमाणित सूची मांगी थी लेकिन आयोग की और से कोई सूची उपलब्ध नही करवाई गई और लगातार आरटीआई कार्यकर्ता से पत्र व्यवहार कर अलग-अलग एजेंसी से जानकारी मांगने को कहा गया। मामला मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली तक गया लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी नही मिली। उक्त मामले के बाद उम्मीद थी कि निर्वाचन आयोग इस बार मामले का संज्ञान लेकर वर्षो से जमे अधिकारीयो का स्थानांतरण नियमानुसार लोकसभा क्षेत्र के बाहर करेगे लेकिन इस बार भी निर्वाचन की ओर से कोई बड़ी कार्यवाही देंखने को नही मिली और अधिकारी जस का तस उसी स्थान पर जमे हुए है । आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण कुमार मालवीय ने बताया कि, आज भी जिले में वही अधिकारी है जो वर्षो से जमे हुए है । पेटलावद विकास खण्ड में तो ऐसे भी अधिकारी है जो इसी विकास खण्ड ओर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले है । निर्वाचन आयोग द्वारा आज तक कलेक्टर की अनुमोदित सूची उपलब्ध नही करवाई गई जो समय से पूर्व निर्वाचन आयोग के पास पहुँच जानी थी। जिससे साफ है कि चुनाव की प्रक्रिया में भारी लापरवाही की जा रही है । मालवीय ने कहा कि चुनावी खर्च को लेकर मामला हाईकोर्ट में मेरे द्वारा लगा हुआ है और ये मामला भी न्यायालय में लेकर जाऊँगा।

यह चुनावी साल का राजनीतिक भगोरिया पर्व...

माही की गूंज़, झाबुआ।

इन दिनों अंचल में भगोरिया मेलों की धूम मची हुई है। वैसे तो आदिवासियों का यह त्यौहार हर वर्ष परंपरागत तौर पर आदिवासी संस्कृति के साथ सादगी व उल्लास से मनाया जाता है। आदिवासी समाज की अपनी अलग ही अनौखी संस्कृति का यह पर्व यू तो विश्व भर में विख्यात है। वर्तमान समय में वैसे तो अब हर आदिवासी क्षेत्र में भगोरिया हाट मनाए जाने लगे है। लेकिन मूलतरू भगोरिया का यह त्यौहार झाबुआ जिले की मूल संस्कृति रही है। वर्तमान में जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो भगोरिया हाट आयोजित हो रहे है, असल में वे कभी भगोरिया हाट थे ही नहीं, वे तो गुलालिया हाट कहे जाते थे, लेकिन अब इन गुलालिया हाटों को भी भगोरिया का नाम दे दिया गया। झाबुआ जिले में होली के पहले आठ दिनों में हर रोज अलग-अलग जगह पर भरने वाले यह हाट बाजार भगोरिया पर्व के रूप में मनाए जाते रहे है।

आदिवासियों के इस त्यौहार को पूरे समाज द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इसमें बहुत अधिक भीड़ उमड़ती है। राजनीतिक परिदृश्य में आदिवासियों की संस्कृति का फायदा उठाने की कोशिशें राजनीतिक दल करते दिखाई पड़ते है। जब-जब चुनाव के आसपास यह त्यौहार आता है इसमें जमकर राजनीति होती नजर आती है। भगोरियों में उमड़ती भीड़ में हर राजनेता अपनी ताकत दिखाने की कोशिशें करता है। राजनीतिक दलों द्वारा इन भगोरिया हाटों में शक्ति प्रदर्शन के लिए गैर भी निकाली जाती है। चुनावी साल में आने वाले भगोरिया हाट कुछ अलग ही दिखाई पड़ते है। फाग का रंग, भगोरिये की मस्ती, उल्लास और अलहड़पन के साथ राजनीतिक भांग इन भगोरिया हाटों को एक अलग ही रंग दे देती और भगोरिया उत्सव में उमड़ने वाली भीड़ राजनीतिक दलों के हिसाब से बट जाती। हालांकि जब चुनाव नहीं होते और भगोरिया आता है तो स्थितियां ठीक इसके विपरीत दिखाई पड़ती है। उस समय इन भगोरिया हाटों में सिर्फ उल्लास ही उल्लास नजर आता है। नेतागिरी और राजनीति इससे कोसों दूर नजर आती है। राजनीतिक हंगामें भी उस स्तर के देखने को नहीं मिलते। यह तो सिर्फ चुनाव के मौसम में ही दिखाई देते है।

चुनावी सीजन का भगोरिया

इस बार आदिवासी परंपरा का यह भगोरिया त्यौहार चुनावी सीजन में ही आया है। विधानसभा चुनाव निपट चुके है और अब लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। चुनावी सरगर्मियां तेज है और ऐसे में भगोरिया पर्व का

- फाईल फोटो भगोरिया

आना मतलब नेताओं और चुनावी प्रत्याशियों का बड़ा फायदा। इन आठ दिन के भगोरियों में हर राजनीतिक दल का नेता अपनी पार्टी प्रचार में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगा। जो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी घोषित हो चुके है और जो नहीं हुए है सब के सब होली के पहले तक लगने वाले इन भगोरिया हाटों की खाक छानते फिरेंगे। आदिवासी समाज के मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर आजमाईश होगी। त्यौहार की आड़ में पूरे तरीके से चुनाव प्रचार होगा। राजनीतिक दलों द्वारा शराब बांटी जाएगी और पैसा भी खर्च किया जाएगा।

राजनीकि दल खरीद लेते है ढोल-मांदल की टोलियां

वैसे तो इस त्यौहार यानि भगोरिया में आदिवासी समाज द्वारा परंपरागत वाद्ययंत्रों का उपयोग किया जाता रहा है। ढोल, मांदल, थाली और बांसूरी इनमें मुख्य होते है। मगर इन वाद्य यंत्रों को बजाने वाली टोलियां अब राजनीति का शिकार हो चली है। पहले यही टोलिया फागुन की मस्ती में भगोरिया हाटों में जगह-जगह स्वतंत्र रूप से दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब राजनीतिक दल इन्हे पैसे देकर पहले ही बुक कर लेते है। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि राजनीतिक दल जो गैर इन भगोरिया हाटों में निकालते है उनमें शामिल होने के लिए इन टोलियों को पैसे देकर खरीद लिया जाता है। जिस राजनीतिक दल की गैर में इन ढोल-मांदल वाली टोलियों की संख्या ज्यादा होती उसे ही वर्चस्व वाली पार्टी माना जाता है। हालांकि इन राजनीतिक गैरों में उमड़ने वाली भीड़ का कोई ठोर नहीं है। जो भीड़ एक राजनीतिक दल की गैर में दिखाई पड़ती, थोड़ी देर बाद वही भीड़ दूसरे राजनीतिक दल की गैर में दिख जाती।

तेरी भी जय, मेरी भी जय

यहां एक बात को स्पष्ट हो जाती है कि अब इस आदिवासी बाहुल जिले की जनता भी समझदार हो चली है। वह अपने पर किसी का ठप्पा नहीं लगने देना चाहती और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए यहां श्तेरी भी जय मेरी भी जय्य वाली काहनी देखने को मिल रही है। भगोरिया हाटों में नेताओं की यह बहार सिर्फ चुनावी सालों में ही देखने को मिली है। बाकी सालों में यह इस त्यौहार से खासी दूरी बनाए दिखाई पड़ते है। हालांकि लोकसभा चुनाव सर पर है और यह जिले में भगोरिया उत्सव का समय है तो अब देखने वाली बात तो यही होगी कि कौन किसको कितना प्रभावित कर पाता है।

बहती गंगा में हाथ धोता पुलिस विभाग

आदिवासी बाहुल जिले की अधिकतर आबादी वैसे तो साल के अधिकतम समय पलायन पर रहती है। मगर होली के पहले पड़ने वाले भगोरिया उत्सव में शामिल होने के लिए जिले की लगभग शत-प्रतिशत आबादी वापस अपने घर लौट आती है। यह समय ऐसा है कि भगोरिया की मस्ती में डूबने के लिए हर कोई अपने घर लौट आता है। ऐसे में वे अपराधी भी जिले में वापस आते है जो किसी घटना को अंजाम देकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते है। या फिर लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते है। अब पुलिस इन भगोरिया हाटों का फायदा उठाते हुए अपराधियों की तलाश कर धर पकड़ कर रही है। मतलब सीधा सा है कि पुलिस विभाग भी भगोरिया की मस्ती में बहती गंगा में हाथ धोता नजर आ रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422